पेज 09 में...

श्रमिकों के 22 बच्चे दसवीं बारहवीं की मेरिट लिस्ट में...

साप्ताहिक

शहर सत्ता

PRGI NO. CTHIN/25/A2378

सोमवार, 08 जून से 14 जून 2026

हम दिखाएंगे आईना...

पेज 12 में...

मासूम सुमना तुझे सलाम

वर्ष : 02 अंक : 14 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 09 जशपुर में जल संरक्षण बना जन आंदोलन

जांच की आस में टूटती सांस...

- स्ट्रेचर पर दम तोड़ती चिकित्सा व्यवस्था
- सरकारी अस्पतालों में प्रतीक्षा सूचि लंबी
- प्राइवेट में आसमान छूती फीस से मरीज बेजार
- सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़ रहा
- गंभीर बीमारी ही नहीं छोटे-मोटे ऑपरेशन भी मुश्किल

प्रदीप चंद्रवंशी/शेख आबिद
रायपुर

"डॉक्टर साहब, अभी तो आए हैं, अगली तारीख दे दी... अब तीन महीने बाद आना।" एक मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों ही आपदाओं में एक परिवार का पूरा बजट ध्वस्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शासन के पास इन दोनों ही समस्याओं के लिए कोई योजना नहीं है। लेकिन हेल्थ और एजुकेशन के लिए सरकार की योजना का मौके पर लाभ नहीं मिलता। आज भी आम आदमी कर्ज लेकर ही इन चुनौतियों से खुद जद्दोजहद कर रहा है। मुफ्त की जमीन में एम्स, बड़े-बड़े सरकारी अस्पताल और महंगी मशीनों के बावजूद अब भी जरूरतमंद मरीज तरस रहे हैं। सरकारी की तुलना में नीजि अस्पताल का कारोबार पूरे उरूज़ पर है। हालांकि नीजि अस्पताल भी पैसा रहते तक ही अपने मरीज को ज़िंदा रख पाता है। खेल ख़त्म तो पैसा हज़म ! लब्बोलुआब यह कि छत्तीसगढ़ में चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर आज भी स्ट्रेचर में ही दम तोड़ रहा है। करोड़ों की दवाएं खरीदने के बाद भी लोगों को महंगी दवाएं बाहर से खरीदना पड़ता है। जांच के लिए करोड़ों रूपये की मशीनें हैं पर जांच के लिए लंबी वेटिंग है।

शहर सत्ता पड़ताल/रायपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) या डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय (मेकाहारा) के गलियारों में यह संवाद आम है। एक मरीज, जो अपनी बीमारियों से पहले सरकारी तंत्र की लेटलतीफी और संसाधनों की कमी से लड़ रहा है, वह हर दिन इस उम्मीद में खड़ा होता है कि शायद आज नंबर आ जाए। यह स्थिति केवल रायपुर की नहीं, बल्कि देश के अधिकांश सरकारी मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों की है। जहाँ एक ओर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है, वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों का भारी-भरकम बिल मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ रहा है।

केस स्टडी 1: जांच में 'तीन महीने' की प्रतीक्षा और आर्थिक बोझ

मरीज का नाम (बदला हुआ): राम यादव
स्थान: रायपुरा, रायपुर
समस्या: पथरी (Stone) की बीमारी।

विवरण: राम यादव जब एम्स रायपुर की ओपीडी में अपनी पथरी की समस्या लेकर पहुंचे, तो डॉक्टरों ने उन्हें आवश्यक सोनोग्राफी जांच की सलाह दी। उम्मीद थी कि एक केंद्रीय संस्थान होने के नाते यहां उन्हें किफायती और त्वरित इलाज मिलेगा। लेकिन, जब वे जांच काउंटर पर पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि सोनोग्राफी के लिए तीन महीने की लंबी वेटिंग है।

परिणाम: अपनी पीड़ा कम करने के लिए राम यादव को मजबूरी में बाहर की निजी लैब का सहारा लेना पड़ा। निजी लैब की महंगी फीस ने उनके आर्थिक बजट को बिगाड़ दिया। एम्स की ओपीडी में परामर्श के बावजूद, केवल जांच के लिए महीनों का इंतजार और अंततः बाहर से निजी जांच कराना इस बात का प्रमाण है कि संस्थान के पास न तो पर्याप्त उपकरण हैं और न ही मैनपावर।

केस स्टडी 2: गरीबी ही बनी इलाज से 'इनकार' का कारण

मरीज का नाम (बदला हुआ): रिया (12 वर्ष)

स्थान: दंतेवाड़ा

समस्या: न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर (मायोक्लोनिक झटके और बेहोशी के दौरे)।

विवरण: पिछले चार महीनों से रिया गंभीर व्यवहारिक बदलाव और बेहोशी के दौरों से जूझ रही थी। एम्स के डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में 'सबएक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफलाइटिस' जैसी गंभीर बीमारी का संदेह जताया। यहाँ तक कि परिवार के पास आयुष्मान भारत कार्ड और बीपीएल श्रेणी का प्रमाण भी था।

परिणाम: एम्स प्रशासन ने इस मासूम बच्ची को भर्ती करने के बजाय मेकाहारा (अंबेडकर अस्पताल) रेफर कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि रेफरल पर्ची में कारण के तौर पर 'आर्थिक समस्या' दर्ज किया गया। एक केंद्रीय संस्थान द्वारा मरीज को 'गरीब' मानकर इलाज से वंचित कर देना न केवल सरकारी योजनाओं की असफलता को दर्शाता है, बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं का भी घोर उल्लंघन है।

केस स्टडी 3: सांसे चल रही थी कर दिए मृत घोषित, एम्स से मित्तल हॉस्पिटल रिफर

मरीज: भिलाई निवासी एक युवक

स्थान: एम्स रायपुर (रेफरल पॉइंट) से मित्तल अ

विवरण: यह घटना एम्स के रेफरल सिस्टम और के बीच की एक दर्दनाक कड़ी है। एम्स से मेकाह बेहतर इलाज की उम्मीद में मरीज को मित्तल अ कि अस्पताल ने युवक को मृत घोषित कर उनकी बॉडी उन्हें सौंप दी। लेकिन अंतिम संस्कार के रास्ते में युवक के शरीर में हरकत दिखाई दी।

विवाद का पक्ष: इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। परिजनों ने अस्पताल पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं, अस्पताल प्रबंधन (डॉ. आशीष मित्तल) का तर्क है कि मरीज की हालत बहुत गंभीर थी, उन्हें मृत घोषित नहीं किया गया था, बल्कि परिजन खुद मरीज को ले गए थे और 'LAMA' (लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस) फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे।

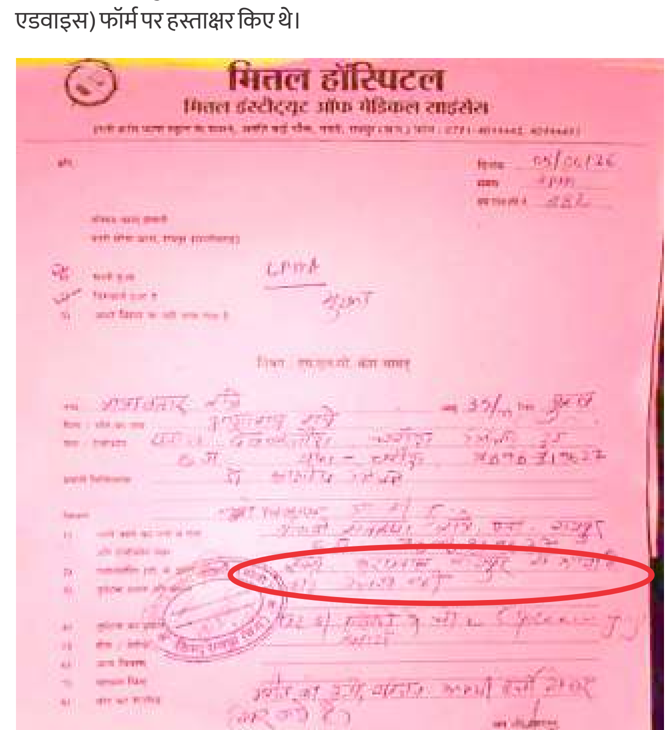
मित्तल हॉस्पिटल
मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस
LAMA

सरकारी अस्पतालों का 'महामंथन'
मरीजों का सैलाब और सीमित संसाधन

एम्स (AIIMS) और अम्बेडकर अस्पताल जैसे संस्थान स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ माने जाते हैं। यहां न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों से भी मरीज आते हैं। लेकिन समस्या यह है कि मरीजों की संख्या के अनुपात में संसाधन और डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। ओपीडी (OPD) से लेकर ऑपरेशन तक: एक सामान्य ओपीडी पर्ची कटाने के लिए सुबह 4 बजे से लाइन में लगना पड़ता है। यदि डॉक्टर ने किसी बड़ी जांच की सलाह दी, तो वह तारीख दो महीने बाद की मिलती है और अगर ऑपरेशन की बात हो, तो वेटिंग लिस्ट छह महीने से एक साल तक पहुंच जाती है।

संसाधनों का अभाव

एमआरआई (MRI), सीटी स्कैन (CT Scan) और डायलिसिस जैसी जरूरी जांचों के लिए मशीनों की संख्या मरीजों के दबाव के सामने नगण्य है। मशीनें खराब होना या मेंटेनेंस के नाम पर बंद रहना एक आम बात हो गई है, जिससे परेशान मरीज मजबूरन बाहर से महंगी जांच करवाते हैं।

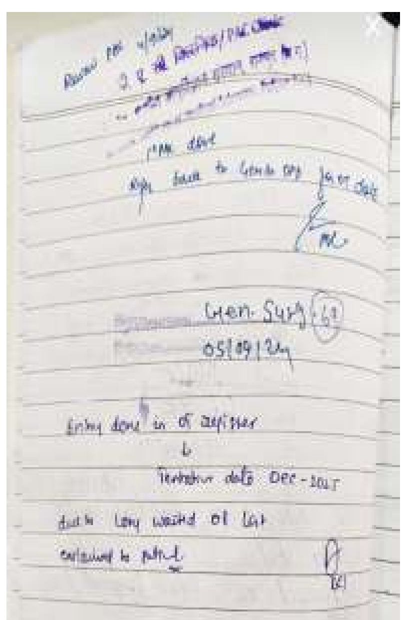

एम्स में संभावित वेटिंग लिस्ट (अनुमानित)

सेवा का प्रकार	बीमारी / जांच का विवरण	अनुमानित वेटिंग समय
निदान (Diagnostics)	सोनोग्राफी (USG)	1 से 3 महीने
निदान (Diagnostics)	सीटी स्कैन (CT Scan)	1 से 2 महीने
निदान (Diagnostics)	एमआरआई (MRI)	3 महीने से 1 वर्ष तक*
सर्जरी (Surgeries)	सामान्य सर्जरी (General Surgery)	2 से 3 महीने
सर्जरी (Surgeries)	कार्डियो-थोरेसिक/न्यूरो सर्जरी	6 महीने से 2 वर्ष तक
सर्जरी (Surgeries)	सर्जिकल ऑन्कोलॉजी (कैंसर)	3 से 6 महीने
परामर्श (OPD)	ओपीडी पंजीकरण (दैनिक)	उसी दिन

***नोट: एमआरआई जैसी बड़ी और गंभीर जांचों के लिए सरकारी अस्पतालों में लंबी लाईन के चलते मरीजों को निजी लैब का सहारा लेना पड़ता है।**

निजी अस्पताल: बेहतर इलाज, लेकिन 'पहुंच' से कोसों दूर

जब सरकारी अस्पतालों की लंबी वेटिंग मरीज को 'मौत के करीब' ले जाती है, तो वह मजबूरन निजी अस्पतालों (Private Hospitals) का रुख करता है। निजी अस्पतालों में प्रवेश करते ही उसे साफ-सफाई, त्वरित उपचार और आधुनिक मशीनें तो मिलती हैं, लेकिन इसके साथ ही आता है 'बिल का सदमा'।

मध्यम वर्ग की त्रासदी

एक मध्यम वर्गीय परिवार, जिसके पास न तो बीपीएल (BPL) कार्ड है और न ही कोई बड़ा स्वास्थ्य बीमा, उसके लिए निजी अस्पताल में एक हफ़्ते का इलाज भी पूरी जमा-पूंजी खत्म करने के लिए काफी है।

इलाज का व्यवसायीकरण

कॉर्पोरेट अस्पतालों में इलाज की प्रक्रिया अक्सर लाभ-केंद्रित (Profit-centric) होती है। दवाइयों की कीमत, बेड चार्ज, और अनावश्यक जांचें बिल को इतना बढ़ा देती हैं कि परिवार को अपनी संपत्ति तक गिरवी रखनी पड़ जाती है। 'गरीब के लिए स्वास्थ्य' एक ऐसा सपना बनकर रह गया है जो कागजों पर तो है, लेकिन धरातल पर निजी अस्पताल अमीरों की 'आरामगाह' बन चुके हैं।

क्यों है ये अंतर? एक खोखला सिस्टम

सरकारी अस्पतालों में भीड़ का सबसे बड़ा कारण 'रेफरल सिस्टम' का ठीक से काम न करना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में अगर इलाज सही तरीके से हो, तो बड़े अस्पतालों का बोझ आधा हो जाए। लेकिन वहां न तो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और न ही दवाइयाँ। परिणामस्वरूप, एक छोटी सी सर्जरी के लिए भी मरीज सीधे एम्स या बड़े सरकारी अस्पतालों में दौड़ता है। दूसरी तरफ, निजी अस्पतालों को सरकारें टैक्स में छूट और सस्ती दरों पर जमीन देती हैं, लेकिन बदले में वे 'गरीबों का कोटा' या 'सस्ता इलाज' सुनिश्चित करने के वादों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।

क्या हैं समाधान की राहें?

जिला अस्पतालों को सशक्त बनाना

जब तक जिला स्तर पर एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी सुविधाएँ सुचारू नहीं होंगी, तब तक एम्स जैसे संस्थानों पर दबाव कम नहीं होगा।

पीपीपी मॉडल का सही क्रियान्वयन

सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच एक ऐसा संतुलन बनाना होगा जहाँ सरकार की निगरानी में निजी अस्पताल रियायती दरों पर मरीजों का इलाज करें।

स्वास्थ्य बजट में वृद्धि

केंद्र और राज्य सरकारें भारत में अभी भी अपनी जीडीपी का एक छोटा हिस्सा ही स्वास्थ्य पर खर्च करता है। इसे बढ़ाकर कम से कम 3-4% करना अनिवार्य है।

डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड

लंबी वेटिंग का एक कारण पुराने रिकॉर्ड न मिलना भी है। एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस होने से मरीज की रिपोर्ट कहीं भी देखी जा सकेगी, जिससे अनावश्यक जाँचों पर खर्च कम होगा।

वेटिंग लिस्ट प्रभावित करने वाले कारक

मरीज की गंभीरता (Triage System): इमरजेंसी (जैसे एक्सीडेंट, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक) में आने वाले मरीजों को बिना किसी वेटिंग के प्राथमिकता दी जाती है। वहीं, जो मरीज रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, उन्हें लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ता है।

विभागों में रिक्त पद: जैसा कि आपने बताया, एम्स में डॉक्टरों और तकनीकी स्टाफ के सैकड़ों पद खाली हैं। स्टाफ की कमी के कारण मशीनों का संचालन 24/7 नहीं हो पाता, जिससे वेटिंग लिस्ट बढ़ती जाती है।

मशीनों की उपलब्धता और मेंटेनेंस: सर्वर ठप होने या तकनीकी खराबी के समय पूरी प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे उस दिन के सभी अपॉइंटमेंट आगे शिफ्ट हो जाते हैं।

वीआईपी कल्चर: वीआईपी रेफरल या प्रभावशाली व्यक्तियों की सिफारिश के चलते कई बार आम मरीजों की वेटिंग लिस्ट प्रभावित होती है।

चिटफंड फर्मों की 200 करोड़ की संपत्ति कुर्क पर नीलामी नहीं

2 वर्ष से पीड़ितों के हाथ खाली, राहत दिलाने सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 15 साल में 30 लाख से ज्यादा लोगों की खून-पसीने की कमाई चिटफंड कंपनियों ने डकार ली। आंकड़े के मुताबिक प्रदेशभर के निवेशकों के 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा डूबे हैं, पर तमाम कोशिशों के बाद अब तक 5.16 लाख लोगों को ही 98 करोड़ रुपए ही वापस मिल सके। यानी महज 5% हिस्सा। इस कछुआ रफ्तार की सबसे बड़ी वजह यह है कि चिटफंड कंपनियों की प्रॉपर्टी या तो अटैच नहीं हो पा रही है, या जो अटैच हुई उसकी नीलामी अटक गई है। कंपनियों की 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर जिला अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से 'स्टे' लगा हुआ है। प्रॉपर्टी नहीं बिक पाने से पिछले दो साल से पीड़ितों की रकम वापसी ठप है।

अब इस गतिरोध को तोड़ने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका दायर करने जा रही है। इसमें प्रदेशभर में मौजूद चिटफंड कंपनियों की प्रॉपर्टी की बिक्री का रास्ता साफ करने और सभी तरह के 'स्टे' हटाने की मांग की जाएगी। करीब 15 साल पहले हर जिले में 7000 से ज्यादा छोटी-बड़ी फर्जी कंपनियां आई थीं। रायपुर में ही 66 कंपनियों में 800 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ और सभी रातों-रात भाग गईं। 2018 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नया अधिनियम बनाकर निवेशकों का पूरा पैसा लौटाना सुनिश्चित करने का दावा किया था, पर 98 करोड़ रुपए ही लौटे। इसके बाद भाजपा सरकार बनी, पर पीड़ितों को रकम वापसी का काम बंद है। 2002 में पहली एफआईआर हुई, किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया 2002 में रायपुर के डीडी नगर में एक चिटफंड कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन तब प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि अगले 5 साल में पूरे राज्य में चिटफंड कंपनियों का जाल बिछ गया। अभी राज्यभर में 220 से ज्यादा अनियमित चिटफंड कंपनियों के खिलाफ करीब 490 एफआईआर दर्ज हैं। इनमें से 265 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं, जबकि 80 कंपनियों के 66 से ज्यादा डायरेक्टरों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन रकम वापसी का तंत्र अब भी नाकाम है।

इन कंपनियों की प्रॉपर्टी की जानकारी, लेकिन कुर्क ही नहीं हुई

सनशाइन इंफ्रा बिल्ड- 50 लाख की संपत्ति, भाटापारा के गांव में कंपनी के डायरेक्टर के नाम पर 20 एकड़ जमीन। पीएसीएल- 110 करोड़ की संपत्ति, कृष्णा कांप्लेक्स में 1.50 करोड़ का ऑफिस। धमतरी, मनेंद्रगढ़, रायगढ़ में जमीन। एचबीएन- 100 करोड़ संपत्ति, रायपुरा चौक पर अधूरा शॉपिंग मॉल 60 लाख का। धमतरी और गरियाबंद में जमीन। बीएनपी इंडिया- 46 करोड़ की संपत्तिः अभनपुर के पास 30 एकड़ जमीन। राज्य के दूसरे शहरों में भी जमीन में निवेश। आस्था गोट फार्मिंग- 120 करोड़ की संपत्ति, खरोरा के पास 15 एकड़ जमीन। कुछ और कस्बों में भी प्लाट के मालिक। माइक्रो फाइनेंस- 80 करोड़ की संपत्ति, पुराना धमतरी रोड में 40 एकड़ जमीन। कुछ और कस्बों में भी प्लॉट मौजूद। ग्रीन रे कंपनी- 70 करोड़ की संपत्ति, ओडिशा में कंपनी ने जमीन पर निवेश किया, इसे कुर्क किया नीलामी नहीं हुई।

गैस एजेंसी सुपरवाइजर से 10 लाख की लूट CCTV में कैद हुए बदमाश

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी है। डंगनिया बाजार के पीछे स्थित शांति विहार इलाके में गैस एजेंसी के एक सुपरवाइजर से करीब 10 लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार पीड़ित श्रवण साहू एक एचपी गैस एजेंसी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि वे अपनी कार से नकदी से भरा बैग लेकर बाहर निकल रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे दो बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। आरोपियों ने झपट्टा मारकर रुपयों से भरा बैग छीना और मौके से फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दो संदिग्ध बाइक सवार वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। अधिकारियों का मानना है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंचा जा सकेगा। लूट की सूचना मिलते ही डीडी नगर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस ने इलाके के अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया है। पीड़ित श्रवण साहू की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। शुरुआती जांच में यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपियों को नकदी की जानकारी पहले से थी या नहीं। राजधानी में दिनदहाड़े 10 लाख रुपये की लूट की घटना ने कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यस्त इलाके में इस तरह की वारदात अपराधियों के बढ़ते हौसलों को दर्शाती है।

शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी 18 से 20 सीटर मिनी बस, 45 दिन का ट्रायल

रायपुर। राजधानी की सड़कों पर 8 जून से 18 से 20 सीटर मिनी बसें फर्राटे भरेंगी, आम जनता को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा देने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 8 मिनी बसें संचालित होंगी। इन मिनी बसों का संचालन सीईइडब्ल्यू एनजीओ के द्वारा किया जाएगा, इसमें 45 दिन का ट्रायल रहेगा। रिस्पांस अच्छा मिलने पर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इसका विस्तार किया जा सकता है। 17 से 20 सीटर क्षमता वाली मिनी बसें नगर निगम द्वारा सुझाए गए दो रूटों पर प्रयोग बतौर संचालित होंगी। इनमें से 4 बसें टाटीबंध और शास्त्री चौक होते हुए रेलवे स्टेशन तक जाएंगी। इसी तरह दूसरे रूट में चार मिनी बसें रेलवे स्टेशन से पचपेड़ी नाका होते हुए भाठागांव स्थित नए बस स्टैंड तक यात्रियों को हर 15 से 20 मिनट में उपलब्ध कराने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक नई मिनी बसें संचालित होंगी। छत्तीसगढ़ राजपत्र के अनुसार बस किराया तय रहेगा। राजधानी वासियों को सुगम आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा का नया विकल्प मिलने वाला है। शहर में 8 माइक्रो यानी 18 से 20 सीटर मिनी बसें चलाई जाएंगी। ये बसें टाटीबंध, रेलवे स्टेशन, पचपेड़ीनाका और भाठागांव के आईएसबीटी जैसे क्षेत्रों में संचालित होंगी। दिल्ली की संस्था सीईइडब्ल्यू द्वारा इन बसों का संचालन किया जाएगा। संकरी व कम यात्री संख्या वाले मार्गों पर भी सार्वजनिक परिवहन की पहुंच बढ़ाने का प्रयास रहेगा। खासकर के छात्रों, नौकरीपेशा कर्मचारियों, मजदूरों और कम आय वर्ग के यात्रियों को किफायती एसी बस सेवा का लाभ इससे मिलेगा।

सीईडब्ल्यू एनजीओ करेगी संचालन

दो रूट पर 8 मिनी बसों का संचालन

संस्था शुरुआत में 8 मिनी बसों का संचालन करेगी। यह 45 दिन के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रहेगा। इसके बाद संचालन, वित्तीय व्यवहार्यता, यात्रियों की आवश्यकता, व संभावनाओं का आकलन कर किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने परिवहन सचिव से मुलाकात कर स्पेशल परमिट के लिए आग्रह किया था।

शहरों को पहचान देने निकले 834 करोड़ फाइलों से ही बाहर नहीं आए प्रोजेक्ट

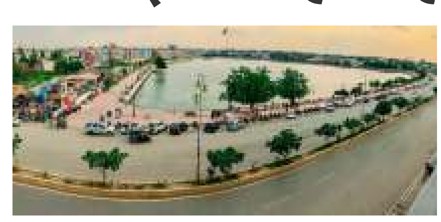

रायपुर। प्रदेश के नगरीय निकायों को पिछले कुछ महीनों में दो बड़ी योजनाओं के तहत 834 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिल चुकी है। इनमें मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के 429.45 करोड़ रुपए और 15वें वित्त आयोग की 404.66 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। इसके बावजूद अधिकांश निकायों में कामों की गति बेहद धीमी है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 13 नगर निगमों में 26 बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। इनका उद्देश्य शहरों को नई पहचान देने के साथ यातायात, जलापूर्ति, स्वच्छता और शहरी अधोसंरचना को मजबूत करना है। लेकिन जमीनी स्थिति यह है कि कई परियोजनाएं अब तक टेंडर, डीपीआर या प्रारंभिक प्रक्रिया से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। राजधानी रायपुर इसका बड़ा उदाहरण है। यहां 91.27 करोड़ रुपए के चार प्रमुख प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। महादेव घाट पुनरुद्धार, 18 रोड जंक्शन का विकास और गौरवपथ-2 जैसे कामों पर अब तक ठोस प्रगति नहीं दिखी है।

प्रमुख नगर निगमों में स्वीकृत प्रोजेक्ट

रायपुर (91.27 करोड़): महादेव घाट पुनरुद्धार, टेक्नीकल टॉवर, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, 18 रोड जंक्शन।

रायगढ़ (64.66 करोड़): मरीन ड्राइव विस्तार, ऑक्सीजोन-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल।

बिलासपुर (57.92 करोड़): अटल पथ, सड़क चौड़ीकरण, तालाब सौंदर्यीकरण, सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट।

कोरबा (36.55 करोड़): गौरव पथ।

धमतरी (24.64 करोड़): हाइटेक बस स्टैंड, ऑडिटोरियम।

अंबिकापुर (13.99 करोड़): मां महामाया कॉरिडोर, पार्क विकास।

जगदलपुर (19.95 करोड़): दलपत सागर विकास, मार्ग चौड़ीकरण।

भिलाई-चरोदा (29.43 करोड़) : केनाल रोड निर्माण।

डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने वाला देश का पहला शहर बना रायपुर

QR कोड से मिलेगी ऑटो-ई-रिक्शा चालकों की जानकारी

रायपुर। राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस कमिश्नरेट ने ऑटो और ई-रिक्शा वाहनों के डिजिटल पंजीयन अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस अभियान के तहत करीब 15 हजार ऑटो और ई-रिक्शा का डिजिटल पंजीयन किया गया है। इसके साथ ही रायपुर सार्वजनिक परिवहन में संचालित ऑटो और ई-रिक्शा का बड़े पैमाने पर डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है। यह पहल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा और वाहन चालकों की पहचान सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित होगी।

पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में 20 मई से 5 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाया गया।

इस दौरान वाहन चालकों को घर बैठे क्यूआर कोड स्कैन कर निशुल्क पंजीयन की सुविधा दी गई। न तो उन्हें किसी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े और न ही किसी प्रकार का शुल्क देना पड़ा। यातायात पुलिस और ऑटो-ई रिक्शा संघों के संयुक्त प्रयासों से निर्धारित अवधि में लगभग 15 हजार वाहनों का सफल पंजीयन किया गया।

पंजीकृत ई-रिक्शा में विशेष QR कोड

पुलिस अधिकारियों के अनुसार अगले चरण में पंजीकृत ऑटो और ई-रिक्शा में विशेष QR कोड लगाए जाएंगे। कोई भी यात्री मोबाइल से इस कोड को स्कैन कर वाहन मालिक और चालक की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और किसी प्रकार के विवाद, अभद्र व्यवहार या शिकायत की स्थिति में चालक की तत्काल पहचान की जा सकेगी। ऑटो और ई-रिक्शा यूनियन के अनुरोध पर पंजीयन की समय-सीमा को 7 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। जिन वाहन चालकों का अब तक पंजीयन नहीं हो पाया है, उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अतिरिक्त अवधि समाप्त होने के बाद बिना पंजीयन वाले ऑटो और ई-रिक्शा के संचालन पर कार्रवाई की जाएगी।

साप्ताहिक शहर सत्ता

बुआई से पहले किसानों को बड़ा झटका खेती का खर्च प्रति एकड़ 10 हजार बढ़ा

जोताई से कटाई तक सब महंगा, प्रति एकड़ लागत 34 हजार रुपए के पार

रायपुर। खरीफ की बुआई से ठीक पहले किसानों के सामने इस बार हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। खाद संकट, डीजल की बढ़ती कीमतों और मजदूरी दरों में लगातार इजाफे ने खेती की लागत को एक बार फिर ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। स्थिति यह है कि प्रति एकड़ खेती पर करीब 10 हजार रुपए तक अतिरिक्त बोझ बढ़ने का अनुमान है। इसका सीधा असर छोटे और मंझोले किसानों पर पड़ रहा है, जिनमें से कई ने इस बार रेघा खेती से दूरी बनाने का मन बना लिया है।

कृषि के हर चरण में बढ़ी लागत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेत की जोताई से लेकर रोपाई, निंदाई, खाद, कीटनाशक और अंत में कटाई-मिंजाई तक खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। सहकारी समितियों में खाद की सीमित उपलब्धता के कारण किसानों को निजी बाजार का सहारा लेना पड़ रहा है, जहां दाम कहीं अधिक हैं।

खाद और डीजल ने बिगाड़ा बजट

इस बार खाद की आपूर्ति व्यवस्था किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आई है। डीएपी, यूरिया, पोटाश और सुपर फॉस्फेट जैसी जरूरी खादों की उपलब्धता में कटौती के चलते किसानों को खुले बाजार में महंगे दाम चुकाने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही डीजल की कीमतों में वृद्धि का असर ट्रैक्टर और अन्य कृषि कार्यों की लागत पर साफ दिखाई दे रहा है। खेत की तैयारी से लेकर सिंचाई तक हर काम महंगा हो गया है।

मजदूरी और कृषि कार्यों का बढ़ता खर्च

महंगाई का असर खेतिहर मजदूरी पर भी पड़ा है। रोपाई और निंदाई जैसे कामों में मजदूरों की मांग और दर दोनों बढ़ी हैं। किसानों के अनुसार इस कारण रोपाई-निंदाई का खर्च पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है।

सहकारी समितियों में कटौती से बढ़ी मुश्किल

इस वर्ष सहकारी समितियों के जरिए मिलने वाली खाद की मात्रा भी कम कर दी गई है। किसानों को पहले की तुलना में सीमित मात्रा में ही डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि सुपर फॉस्फेट और पोटाश की आपूर्ति भी घटाई गई है। इससे किसानों की निर्भरता निजी दुकानों पर बढ़ गई है।

अलनीनो के असर की चिंता

इन तमाम मुसीबतों के बीच किसानों की चिंता इस साल के मानसून को लेकर दी जा रही चेतावनी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रशांत महासागर की वजह से बनी अलनीनो की स्थिति के कारण मानसून में मध्यभारत में कम बारिश होगी। अगर ऐसा होता है, तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए दोहरी मुसीबत होगी, क्योंकि यहां के 80 फीसदी से ज्यादा किसान सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर हैं।

खाद संकट से किसान परेशान, डीएपी की कमी, नैनो के उपयोग पर फोकस

रायपुर। जमीनी स्तर पर कई जिलों में किसान खाद उपलब्धता को लेकर परेशान हैं, जबकि सरकार इसे डीएपी की अस्थायी कमी बताते हुए वैकल्पिक उर्वरकों से स्थिति संभालने का दावा कर रही है। खरीफ बुआई के अगले 2-3 सप्ताह इस मुद्दे पर सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि तभी स्पष्ट होगा कि अतिरिक्त आपूर्ति और वैकल्पिक खाद किसानों की वास्तविक मांग पूरी कर पा रही हैं या नहीं। यह देखा गया है कि किसानों को पारंपरिक खाद पर ही ज्यादा भरोसा है, नैनो खाद पर कम है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

सरकार किसानों के धान बुआई एवं उत्पादन प्रभावित न हो इस उद्देश्य से तरल नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया का स्टॉक भी समानांतर रूप से भंडारित करने की रणनीति बनाई है। नैनो के प्रति जागरूकता न होने के कारण किसान हिचक रहे हैं। वहीं कृषि विभाग द्वारा आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को नैनो डीएपी उर्वरक के उपयोग हेतु जागरूक किया जा रहा है। कृषि क्रांति की ओर एक कदम" अभियान के अंतर्गत नैनो डीएपी को फॉस्फोरस एवं नाइट्रोजन युक्त उन्नत तरल उर्वरक के रूप में किसानों के बीच प्रचारित किया जा रहा है, जिससे कम लागत में अधिक एवं संतुलित उत्पादन प्राप्त किया जा सके। डीएपी के मामले में भी केवल 60 प्रतिशत पारंपरिक डीएपी और शेष हिस्से के लिए वैकल्पिक उर्वरकों तथा नैनो डीएपी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों को नैनो उर्वरक लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

आगामी खरीफ सीजन 2026 के लिए छत्तीसगढ़ को केन्द्र सरकार द्वारा 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य आवंटित हुआ है। यह वित्तीय वर्ष की खपत 14.62 लाख मीट्रिक टन से 93 हजार मीट्रिक टन अधिक है। जिसमें यूरिया 7.25 लाख, डीएपी 3 लाख, एमओपी 80 हजार, एनपीके 2.5 लाख तथा एसएसपी 2 लाख मीट्रिक टन शामिल हैं। वर्तमान में राज्य में 10.93 लाख मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद का स्टॉक गोदामों और सोसायटियों में उपलब्ध है। किसानों को 1.8 लाख टन खाद वितरित किया गया है। किसानों को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार मामलों में अफसर-कर्मियों के खिलाफ 45 दिन में अभियोजन स्वीकृति

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक या भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट में चालान पेश करने से पहले राज्य सरकार या नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी से अभियोजन स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था के तहत संबंधित विभागों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। यदि किसी मामले में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, तो उसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अभियोजन स्वीकृति जारी करनी होगी। इसके बाद विधि विभाग मामले का परीक्षण करेगा और आवश्यक अभिमत देगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया अधिकतम 90 दिनों के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा। राज्य शासन ने भ्रष्टाचार के मामलों में समय-सीमा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

रेत खदानों पर पहली बार 50 लाख से अधिक जुर्माना

रायपुर। रायपुर जिले में पहली बार रेत खदानों पर अवैध और नियमों के विरुद्ध उत्खनन किए जाने पर खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी खदानों को बंद कराते हुए बड़ी संख्या में हाईवा तथा चेनमाउंटेन मशीनों को जब्ती बनाया था। इस कार्रवाई से रेत कारोबारियों में हड़कंप भी मचा था। एक साथ सभी खदानें बंद होने से रेत की सप्लाई भी पर खासा असर पड़ा था, इस कार्रवाई के लगभग सप्ताहभर बाद विभाग ने जब्ती बनाए गए सभी हाईवा एवं मशीनों के मालिकों से जुर्माना राशि वसूली करने के बाद वाहन तथा मशीनों को छोड़ दिया है। वहीं बंद खदानों को भी चालू करने का आदेश जारी कर दिया है।

जिले में वर्तमान में रेत की 6 खदानें ही वैध हैं। इन खदानों में भी नियमों के विरुद्ध रेत का उत्खनन तथा निर्धारित क्षेत्र से अधिक जगहों पर रेत का खनन किया जा रहा था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए विभाग ने आधा दर्जन से अधिक चेन माउंटेन मशीन तथा बड़ी संख्या में गाड़ियां पकड़ी थीं। इन सभी मशीन एवं गाड़ियों के मालिक से 50 लाख रुपए से अधिक जुर्माना राशि वसूल की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक चेनमाउंटेन मशीन पकड़े जाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया जाता है, वहीं रेत से भरी प्रति हाईवा पर 28 से 30 हजार रुपए का जुर्माना है।

पर्यावरण-खनिज विभाग की गाइड लाइन के अनुसार खदानों में मशीन के जरिए रेत का उत्खनन एवं वाहन में लोडिंग किया जाना प्रतिबंधित है। इसके बाद भी खदानों में लगातार मशीनों के माध्यम से न केवल उत्खनन किया जा रहा है, बल्कि मशीनों से ही वाहन में रेत लोडिंग कराई जा रही है। विभाग ने मशीनों की जब्ती की और पहली बार 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका। समझौते के बाद फिर से रेत खनन शुरू कर दिया गया है।

15 तारीख से खनन पर लगेगी रोक, इसलिए कार्रवाई नहीं

बारिश के सीजन में हर साल खदानों पर 10 से 15 जून के बीच से लेकर 10 से 15 अक्टूबर तक रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगता है, जो इस बार भी रहेगा। विभाग ने जरूर पखवाड़े भर पहले सख्त कार्रवाई कर खदानों को बंद किया था, लेकिन अब जब दोबारा खदानों में नियमों के विरुद्ध खनन कार्य हो रहे हैं, तो इसे बंद कराने में विभाग द्वारा भी अनदेखा किया जा रहा है। इसका एक ही कारण है बारिश का सीजन।

पांच हजार से ज्यादा रीडर होंगे बेरोजगार

मीटर से ही तैयार हुआ स्मार्ट बिल, बचेंगे हर माह छह करोड़

रायपुर। प्रदेश में अब बिजली उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग को भी स्मार्ट किया जा रहा है। इस महीने पहली बार इसका सफल ट्रायल किया गया। स्मार्ट मीटरों की रीडिंग सीधे कंट्रोल रूम से बैठकर की जा रही है। उपभोक्ताओं को सीधे उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से बिल भेजा जा रहा है। सफल प्रयोग के बाद आने वाले समय में ऑनलाइन रीडिंग का ही सिस्टम चलेगा।

इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी को बिजली नियामक आयोग से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन रीडिंग सिस्टम से पॉवर कंपनी को माह करीब छह करोड़ की बचत होगी। वहीं दूसरी ओर करीब 5000 रीडर बेरोजगार हो जाएंगे। केंद्र सरकार की योजना के तहत छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। प्रदेश के 65 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं में से करीब 35 लाख के मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। बचे मीटरों को भी बदलने का काम चल रहा है, लेकिन अब किसी भी उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। पहले सभी उपभोक्ताओं के मीटरों को बदलने के बाद कनेक्शनों को प्रीपेड करने की योजना थी। लेकिन अब यह योजना खटाई में पड़ गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने खुद ही इसको रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटरों को लेकर विवाद के बाद यह बात सामने आई कि एक्ट में प्रीपेड का प्रावधान ही नहीं है। ऐसे में ऊर्जा मंत्रालय को अपना पुराना आदेश बदलना पड़ा है।

मीटर से सीधे कंट्रोल रूम में रीडिंग

अब गुढ़ियारी के कंट्रोल रूम से सीधे उपभोक्ताओं की माह के अंतिम दिन की रीडिंग देखकर बिल आएगा। ऐसा ही जून के बिल में किया गया है। ऐसा होने से 30 दिनों के स्थान पर ज्यादा दिनों में रीडिंग होने की शिकायत भी नहीं रहेगी। इसका बड़ा फायदा पॉवर कंपनी को यह होगा कि उसके हर माह करीब छह करोड़ बचेंगे। इस समय प्रदेश में 65 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं। इनकी रीडिंग करने के लिए रीडरों को शहरों से ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 12 रुपए प्रति कनेक्शन के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। ऐसे में हर माह करीब छह करोड़ खर्च होते हैं।

पेपरलेस बिलिंग की तैयारी

छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी पेपरलेस बिजली बिल पर काम कर रहा है। जून में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को सीधे उनके मोबाइल पर बिल भेजा गया है। इससे एक बड़ा फायदा यह है कि उपभोक्ताओं को रीडरों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अक्सर रीडिंग गलत होने की शिकायत भी रहती है। ऐसी शिकायत भी नहीं रहेगी। वहीं मकान बंद होने पर औसत रीडिंग के बाद होने वाले विवाद खत्म हो जाएंगे।

संपादकीय

सुकांत राजपूत

व्यवस्था पर चोट या सिर्फ रील्स चमकाने का स्टंट?

हाल ही में राजनीति के गलियारों में उभरी 'कॉकरोच पार्टी' के हालिया प्रदर्शन और आंदोलनों ने मुख्यधारा की राजनीति और आम जनता दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। खुद को 'अंधेरे और संकट में भी जीवित रहने वाली' और 'अजेय' शक्ति के रूप में पेश करने वाली इस पार्टी का प्रदर्शन पहली नज़र में भले ही आक्रामक और ध्यानाकर्षक लगे, लेकिन एक गंभीर राजनीतिक विश्लेषक और जागरूक नागरिक के तौर पर इसके गहरे निहितार्थों को समझना बेहद ज़रूरी है।

'कॉकरोच' नाम अपने आप में एक कड़ा व्यंग्य है। यह पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि जिस तरह एक कॉकरोच परमाणु युद्ध में भी जीवित रह सकता है, उसी तरह वे आम जनता के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हर तरह की महंगाई, बेरोज़गारी और प्रशासनिक उपेक्षा के बावजूद किसी तरह 'सरवाइव' (जीवित) कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महज़ एक अनोखे नाम और प्रतीकात्मक नारों के दम पर गंभीर राजनीति की जा सकती है? हालिया प्रदर्शनों में भीड़ जुटाने और सोशल मीडिया पर रीलें चमकाने में तो पार्टी सफल रही, लेकिन जब बात बुनियादी समस्याओं के ठोस समाधान की आई, तो मंच से केवल लफ्फाजी ही सुनाई दी।

इस पार्टी के बढ़ते प्रभाव का एक बड़ा कारण जनता के एक हिस्से में व्याप्त 'विवेक का आलस्य' भी है। जैसा कि आज के दौर की राजनीति का चलन बन चुका है, लोग जटिल समस्याओं का कोई रेडीमेड और जादुई समाधान चाहते हैं। 'कॉकरोच पार्टी' इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठा रही है। वे जनता की जायज नाराजगी (रोष) को भुनाने का हुनर जानते हैं। लेकिन उनके पास न तो कोई स्पष्ट आर्थिक नीति है और न ही विकास का कोई ठोस खाका। यह प्रदर्शन व्यवस्था सुधारने के लिए कम, और आने वाले चुनावों में अपनी 'फ्रेंचाइजी' चमकाने के लिए ज्यादा प्रतीत होता है।

आज की राजनीति में प्रदर्शन जमीन से ज्यादा स्क्रीन पर लड़े जाते हैं। इस पार्टी के प्रदर्शनों में भी भारी-भरकम लाउडस्पीकर, यूट्यूब लाइव और इंस्टाग्राम रील्स का पूरा तामझाम दिखाई दिया। जब आंदोलन एक 'ब्रांड' बन जाए और कार्यकर्ता 'फॉलोअर्स' में तब्दील होने लगें, तो वैचारिक गंभीरता पीछे छूट जाती है। कॉकरोच पार्टी का यह प्रदर्शन भी जनक्रांति कम और एक सुनियोजित 'स्टार्टअप' का पीआर (PR) इवेंट ज्यादा लग रहा था। लोकतंत्र में हर नई आवाज़ का स्वागत होना चाहिए, और यदि कोई दल सोई हुई सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है, तो वह उसकी लोकतांत्रिक आज़ादी है। लेकिन जनता को यह याद रखना होगा कि श्रद्धा और अंधविश्वास में वही अंतर है जो प्रेम और गुलामी में होता है। यदि आम नागरिक बिना सोचे-समझे इस प्रदर्शन के पीछे दौड़ने लगेगा, तो एक बार फिर वही होगा जो हमेशा से होता आया है—बाज़ार में धर्म और राजनीति तो ऊंचे दामों पर बिक जाएंगे, लेकिन आम आदमी के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही आएंगे। इस 'कॉकरोच पार्टी' के प्रदर्शन को एक चेतावनी की तरह देखा जाना चाहिए, न कि किसी अंतिम समाधान की तरह।

'बाबा' प्राइवेट लिमिटेड: श्रद्धा को उद्योग में बदलने का नया स्टार्टअप !

खुरचन
हरिदास

बेरोज़गारी और महंगाई सिर पर तांडव कर रही है। सरकारें चिंतित हैं, अर्थशास्त्री चिंतित हैं, आप युवा चिंतित हैं। लेकिन कुछ लोग इस समस्या के समाधान के लिए बाबा प्राइवेट लिमिटेड खोलते हैं। श्रद्धा को उद्योग मे बदलने के प्राचीन फार्मूले का नया स्टार्टअप शुरू किया करते हैं। अब तो दाढ़ी और नारंगी वस्त्र की भी जरूरत नहीं। काशी के इंजीनियर बाबा का लुक भी काम कर जाता है। दो-चार मधुर भजन, हिन्दी और अंग्रेजी में कुछ आध्यात्मिक संवाद और सोशल मीडिया पर लाख-दो लाख फॉलोअर चाहिए। फिर मोक्ष का स्टार्टअप शुरू हो जाता है। इसमें अच्छी-खासी पढ़ी-लिखी लड़कियाँ और महिलाएँ फंस भी जाती हैं। नशीला पदार्थ देकर उनका यौन शोषण करने व अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का खेल शुरु हो जाता है।

आश्रम को दुकान की तरह चलाया जाता है। इस व्यापार के लिए पूंजी की जगह धारा-प्रवाह प्रवचन चाहिए। भक्त दरअसल उपभोक्ता है जिन्हें मोक्ष बेचा जाता है, बाकी सामान अपने-आप बिकता है। मोक्ष ऐसी चीज़ है जिसकी कोई गारंटी नहीं मांगता। साबुन खराब निकले तो ग्राहक शिकायत करेगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिला तो कौन उपभोक्ता अदालत जाएगा? सोचिए भला... हम वैज्ञानिक युग जी रहे हैं। आदमी मंगल ग्रह पर पहुंच रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनुष्य के काम कर रही है। मोबाइल फोन में पूरी दुनिया समा गई है। लेकिन बाबा प्राइटेव लिमिटेड से कभी छुटकारा नहीं पाते। हम डॉक्टर से पूछते हैं कि एमबीबीएस कहाँ से किया है। वकील से पूछते हैं कि डिग्री कहाँ से ली है। पत्रकार से पूछते हैं कि खबर का स्रोत क्या है। लेकिन बाबा से कुछ नहीं पूछते। वह चाहे कल तक पान की दुकान चलाता रहा हो, आज यदि उसने आश्रम खोल लिया है तो हम उसके चरणों में ज्ञान खोजने लगते हैं। करोड़ों की संपत्ति वाले किसी बाबा से कोई नहीं पूछता कि महाराज, यह सब आया कहाँ से? सबसे दुखद बात यह है कि इनके जाल में केवल अशिक्षित लोग नहीं फंसते। अच्छी-खासी पढ़ी-लिखी महिलाएं, शोधार्थी, प्रोफेशनल, नौकरीपेशा लोग भी इनके प्रभाव में आ जाते हैं। लगता है डिग्री तो आधुनिक हो गई, लेकिन विवेक अभी भी मध्यकाल में टहल रहा है।

देश में अंधविश्वास का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा नहीं, बल्कि विवेक का आलस्य है। लोग सोचने की मेहनत नहीं करना चाहते। उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके जीवन की सारी समस्याओं का रेडीमेड समाधान दे दे। नौकरी नहीं लग रही? बाबा हैं। विवाह नहीं हो रहा? बाबा हैं। व्यापार नहीं चल रहा? बाबा हैं। ग्रह खराब हैं? बाबा हैं। ग्रह ठीक हैं? तब भी बाबा हैं। मानो भगवान ने पूरी सृष्टि का ठेका किसी फ्रेंचाइज़ी मॉडल पर इन बाबाओं को दे रखा हो। पुराने समय के संत लोगों को अपने भीतर झाँकना सिखाते थे। नए समय के बाबा लोगों को अपने चरणों में झाँकना सिखाते हैं। पुराने संत अहंकार तोड़ते थे। नए बाबा व्यक्तित्व-पूजा खड़ी करते हैं। पुराने संत अनुयायियों को स्वतंत्र बनाते थे। नए बाबा उन्हें मानसिक रूप से आश्रित बना देते हैं। और यह सब धर्म के नाम पर होता है। धर्म शायद दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ों में से एक है। वह मनुष्य को करुणा, संयम और सत्य का मार्ग दिखाता है। लेकिन जब धर्म बाज़ार में उतरता है तो सबसे पहले सत्य ही बिक जाता है।

आज आध्यात्मिकता भी ब्रांड बन गई है। बाबा के यूट्यूब चैनल हैं। इंस्टाग्राम रीलें हैं। भक्ति के पैकेज हैं। ऑनलाइन दर्शन हैं। डिजिटल आशीर्वाद हैं। अब मोक्ष भी शायद ईएमआई पर मिलने लगे तो आश्चर्य नहीं होगा। और भक्त भी कम दिलचस्प नहीं हैं। वे हर चेतावनी को षड्यंत्र मान लेते हैं। हर आलोचना को धर्म-विरोध मान लेते हैं। हर आरोप को संतों के खिलाफ साजिश बता देते हैं। श्रद्धा और अंधविश्वास में वही अंतर है जो प्रेम और गुलामी में होता है। श्रद्धा प्रश्न पूछ सकती है। अंधविश्वास नहीं। श्रद्धा सत्य खोजती है। अंधविश्वास व्यक्ति की पूजा करता है। श्रद्धा मनुष्य को मजबूत बनाती है। अंधविश्वास उसे शिकार बना देता है।

जय हो हरिदास... हरि अनंत हरि कथा अनंता।

योग्यता पर प्रहार, भविष्य पर वार

डॉ. पवन कुमार शर्मा

भारत में 'पेपर लीक' की निरंतर बढ़ती घटनाएं केवल प्रशासनिक विफलता या वित्तीय भ्रष्टाचार का मामला नहीं है बल्कि यह देश के भविष्य के साथ होने वाला एक गंभीर क्रूर मज़ाक है। एक अदद सरकारी नौकरी या प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिले के लिए दिन-रात एक करने वाले करोड़ों विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति एक मानसिक विभीषिका जैसी है।

हर साल लाखों युवाओं की उम्मीदें, उनके माता-पिता की गाढ़ी कमाई और सालों की तपस्या एक झटके में पेपर लीक के काले बाजार की भेंट चढ़ जाती है। एक सुरक्षित परीक्षा प्रणाली का ढांचा तीन स्तंभों पर टिकता है- गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता। पेपर लीक की घटनाएं दर्शाती हैं कि हमारे तंत्र में इन तीनों ही स्तरों पर गंभीर कमियां हैं। प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर प्रिंटिंग प्रेस, लॉजिस्टिक्स (परिवहन) और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के बीच कई ऐसे 'लीक प्वाइंट्स' होते हैं, जहां सुरक्षा बेहद कमजोर है। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों या निजी एजेंसियों की मिलीभगत से प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर तैरने लगते हैं। दूसरा, पेपर लीक मामले में मजबूत कानून और त्वरित न्याय का अभाव है। राज्य स्तर के कानून इतने लचर हैं कि दोषी कुछ ही दिनों में जमानत पर बाहर आ जाते हैं और दोबारा इसी धंधे में लग जाते हैं। त्वरित और कठोर सजा न होना अपराधियों के हौसले बढ़ाता है। तीसरा परीक्षा लेने वाली एजेंसियों की निजी केंद्रों और आउटसोर्सिंग पर अत्यधिक निर्भरता भी इसका बड़ा कारण है। परीक्षा कराने वाली नोडल एजेंसियों में भी कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे वे बाहरी वेंडर्स पर निर्भर हो जाती हैं। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो परीक्षा की तैयारी का दौर अपने आप में एक उच्च-तनाव की अवधि होती है। जब इस तनाव के बीच पेपर लीक या परीक्षा रद्द होने की खबर आती है तो विद्यार्थी का मानसिक संतुलन बुरी तरह डगमगा जाता है। नीट पेपर लीक के बाद देशभर के राज्यों में जिस तरह से युवा-युवत्तियों के आत्महत्या करने की घटनाएं सामने आईं, वे मानसिक असंतुलन और दबाव का ही परिणाम हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र महीनों, सालों तक 'क्रॉनिक स्ट्रेस' यानी लगातार बने रहने वाले तनाव से गुजरते हैं। जब परीक्षा रद्द हो जाती है तो छात्र 'बर्नआउट' की स्थिति में पहुंच जाते हैं। बर्नआउट का अर्थ है मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट जाना, जिसके बाद दोबारा ऊर्जा जुटाना असंभव सा लगने लगता है। मनोविज्ञान में मार्टिन सेलिगमैन का 'लर्नड हेल्पलेसनेस' का सिद्धांत यहां सटीक बैठता है। जब छात्रों को लगता है कि उनकी कड़ी मेहनत, बुद्धिमत्ता और प्रयासों का परीक्षा के परिणाम से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि अंततः पेपर तो पैसे वाले ही खरीद लेंगे तो वे मान लेते हैं कि परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर हैं। यह सोच उन्हें गहरे डिप्रेशन की ओर धकेलती है और वे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। पेपर लीक होने पर जब सालों की मेहनत शून्य हो जाती है तो छात्रों में 'आईडेंटिटी क्राइसिस' पैदा होता है। इसके साथ ही रिश्तेदारों और समाज के ताने, 'इतने साल से क्या कर रहे हो?' जैसी बातें उनके आत्मसम्मान को पूरी तरह नष्ट कर देती हैं।

तय समय से पहले ही खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट

गर्मी बढ़ी तो AC गाड़ी में बैठ गए अभिजीत दीपके

नई दिल्ली। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भीषण गर्मी के बीच करीबन 3:15 बजे धरना स्थल छोड़कर चले गए. वह सुबह करीब 10:30 बजे धरना स्थल पर पहुंचे थे. इससे पहले 6 मई को शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग को लेकर जंतर-मंतर पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी का धरना निर्धारित समय से पहले ही खत्म हो गया. सुबह करीब साढ़े दस बजे पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके धरना स्थल पर पहुंचे थे. दोपहर में बढ़ती गर्मी के बीच कुछ समय के लिए एसी में भी वह बैठे नजर आए. इसके बाद वह दोबारा प्रदर्शन स्थल पर लौटे, लेकिन करीबन 3.15 पर वहां से रवाना हो गए. शाम 4.15 तक जंतर-मंतर का पूरा प्रदर्शन स्थल खाली हो चुका था. पार्टी को दिल्ली पुलिस से शाम 5 बजे तक धरना जारी रखने की अनुमति मिली हुई थी. सीजेपी का यह पहला प्रदर्शन निर्धारित समय से पहले समाप्त हो गया.

कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म, दीपके ने क्या कहा?

कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो चुका है. अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन खत्म होने के बाद एक्स पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा, 'अपने माता-पिता से मिलने घर जा रहा हूं, उनसे मिले हुए एक साल से ज़्यादा का समय हो गया है. पिछले 15 दिनों में उन्होंने बहुत कुछ सहा है और धमकियों के कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था. मैं उन्हें वापस घर लेकर जा रहा हूं.' वहीं, पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने जंतर-मंतर की एक तस्वीर शेयर की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'भारी संख्या में युवा शांतिपूर्वक तरीके से जुटे'।

युवाओं को गलत दिशा में नहीं जाने देंगेः नितिन नबीन

रांची में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि डिजिटल युग का उपयोग युवाओं को गलत दिशा में ले जाने के लिए नहीं होने दिया जाएगा. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन चल रहा था. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश का युवा अपनी मेहनत और ताकत से देश को आगे बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा कि जो लोग युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर ले जाना चाहते हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि भारत का युवा सकारात्मक राजनीति करेगा. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा. उनका इशारा अभिजीत दीपके की ओर माना जा रहा है, जिन्होंने हाल ही में 'Cockroach Janta Party' नाम से वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल शुरू किया था. दीपके एक पब्लिक रिलेशन ग्रेजुएट हैं और पहले अमेरिका में रह चुके हैं. वे आज सुबह भारत लौटे और दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया. दीपके की सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर भी चर्चा रही है, जहां उनके अकाउंट्स ने कुछ ही हफ्तों में लाखों फॉलोअर्स हासिल कर लिए.बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोग विदेशों में बैठकर भारत के युवाओं को दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत का युवा गांव, खेत, कोचिंग सेंटर और कॉलेजों में रहता है और किसी के प्रभाव में आकर गलत दिशा में नहीं जाएगा.।

ईरान-अमेरिका में आर-पार! बमबारी से भड़का तेहरान

नई दिल्ली। अमेरिका ने शनिवार को ईरान के तटीय इलाके में मौजूद रडार ठिकानों पर अटैक किया है. इससे पहले अमेरिका ने ईरान की तरफ से हॉर्मुज की ओर छोड़े गए ड्रोन को मार गिराया था. ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें मुश्किल भरी हो सकती है. अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को जानकारी दी कि अमेरिकी सेना का मानना है कि ईरान के चार ड्रोन इलाके में समुद्री जहाजों को निशाना बना रहे थे. इसके बाद अमेरिका ने ईरान के निगरानी ठिकानों जिनमें गोरुक और केशम द्वीप शामिल हैं, उनपर हमला किया है. ये दोनों ही हॉर्मुज के बेहद करीब हैं. वहीं, अमेरिका की इस कार्रवाई को ईरान के विदेश मंत्रालय ने 8 अप्रैल को हुए सीजफायर का उल्लंघन करार दिया है. मंत्रालय ने कहा है कि बार-बार ऐसे उल्लंघनों से पता चलता है कि अमेरिका तनाव को कम करने के मूड में नहीं है. उसने चेतावनी दी है कि अमेरिका अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों और तनाव के बढ़ाने की स्थिति का जिम्मेदार होगा।

बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए गृहमंत्री शाह का मास्टर प्लान

घुसपैठियों पर लगाम लगाने को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के सालबगान में एक अहम समीक्षा बैठक की है. उन्होंने सीमावर्ती इलाकों की जमीन की खरीद फरोख्त और निर्माण कार्य के अलावा लेन देन के मामले में कड़ी नजर रखने को कहा है. इसके अलावा उन्होंने पिछले पांच साल के जमीन के रिकॉर्ड की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं. यह जानकारी पीआईबी के हवाले से दी गई है. PIB के मुताबिक, शनिवार को अमित शाह त्रिपुरा के सालबगान में थे. यह वो इलाका है, जहां बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर साझा होती है. यानी कि यह दोनों देशों के सीमा के बेहद ही करीब है. इसी को लेकर अमित शाह ने समीक्षा बैठक की, स्थिति का जायजा लिया. गृहमंत्री ने इस दौरान स्थानीय प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर जिम्मेदारी उठाना होगा. यह सिर्फ सीमा सुरक्षाबलों की जिम्मेदारी नहीं है. शाह ने जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारियों, डीएम से लेकर एसपी, पटवारी और सरपंच तक निर्देश दिए हैं, कि सभी मिलकर एक सुरक्षित जाल बनाएंगे. इसे फुल प्रूफ बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड कहा गया है.

इसके अलावा एक नया मॉडल भी लागू किया जाएगा, जिसे टोटल टेरिटोरियल डिफेंस नाम दिया गया है. यानी इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा रखी जाएगी. सीमा पर रहने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा. साथ ही अवैध हथियारों की तस्करी से लेकर नशे की तस्करी से निपटने के तरीके सिखाए जाएंगे. इलाके में कड़ी सुरक्षा को लेकर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. गृह मंत्रालय जल्द इन इलाकों में सीसीटीवी मॉडल भी लागू करेगी.।

सचिवों के छह महीने के कामकाज की समीक्षा करेगी कांग्रेस

नई दिल्ली। चुनावी राज्यों में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद के बीच कांग्रेस हाईकमान ने अपने संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा शुरू कर दी है. पार्टी ने सभी सचिवों और संयुक्त सचिवों से पिछले छह महीनों के कामकाज का विस्तृत ब्यौरा मांगा है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नेतृत्व ने राज्यों के सह-प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्यों में संगठन को मजबूत करने के लिए किए गए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपें. इस रिपोर्ट के जरिए पार्टी यह आकलन करना चाहती है कि संगठन में नियुक्त पदाधिकारी कितने सक्रिय हैं और उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या योगदान दिया है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के बाद सभी सचिव और संयुक्त सचिव अपने-अपने कार्यों का लेखा-जोखा तैयार करने में जुट गए हैं. उनसे यह जानकारी भी मांगी गई है कि बीते छह महीनों में उन्होंने कितने राज्यों का दौरा किया।

खान सर के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उठ रहे सवाल

डूब जाएगी पांच हजार करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री

पटना के मशहूर टीचर खान सर इन दिनों किसी परीक्षा की तैयारी करवाने की बजाय खुद एक कानूनी इम्तिहान के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. 4 जून 2026 को पटना के कोतवाली थाने में उनके खिलाफ हत्या और फायरिंग का मामला दर्ज हुआ. पुलिस की जांच चल रही है और खान सर की गिरफ्तारी की संभावना पर पूरे बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री की नजरें टिकी हैं. मामला सिर्फ एक मशहूर शिक्षक के भविष्य का नहीं है, बल्कि पटना में पिछले दो दशकों में खड़ी हुई करीब 5,000 करोड़ रुपये की कोचिंग इंडस्ट्री का है. खान सर की पहचान सिर्फ एक शिक्षक की नहीं, बल्कि एक ब्रांड की है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वह गिरफ्तार होते हैं तो इसका असर सिर्फ उनके छात्रों पर ही पड़ेगा, या इससे पूरी पटना कोचिंग इंडस्ट्री की नींव हिल जाएगी?

कौन हैं खान सर और क्यों है इतनी चर्चा?

खान सर का असली नाम फैजल खान है और वह पटना के मुसल्लहपुर इलाके में 'खान सर एकेडमी' चलाते हैं. उनकी पढ़ाने की अलग स्टाइल, यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर और सस्ती फीस ने उन्हें बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश के छात्रों के बीच एक जाना-पहचाना चेहरा बना दिया. उनकी खासियत रही कि वह मुश्किल टॉपिक को देसी अंदाज में समझाते हैं. यही वजह है कि उनके कोचिंग सेंटर पर हर साल लाखों छात्र एडमिशन लेने पहुंचते हैं. पटना के कोचिंग हब में खान सर का सेंटर एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है.

पटना पुलिस ने 4 जून को खान सर और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया. आरोप है कि पटना के एक इलाके में कोचिंग सेंटरों के बीच कॉम्पिटीशन के चलते फायरिंग हुई और एक व्यक्ति की मौत हो गई. इस मामले में खान सर का नाम साजिश और उकसाने के आरोप में जोड़ा गया है. खान सर ने मीडिया से कहा, 'मैं संभाल लूंगा, देखते हैं क्या होता है.' लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. पटना देश के सबसे बड़े कोचिंग हब में से एक है, खासकर IAS, BPSC, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए. रिसर्चगेट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, पटना में लगभग 10,000 से ज्यादा छोटे-बड़े कोचिंग सेंटर हैं, जहां हर साल करीब 2 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं. इस उद्योग का सालाना कारोबार 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा आंका जाता है।

अमेरिका में भारतीय शख्स की हत्या, सिर में मारी गई तीन गोलियां

वाशिंगटन। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक भारतीय शख्स की हत्या कर दी गई. हैदराबाद के 28 वर्षीय एक युवक को कथित तौर पर अमेरिका में पिज्जा डिलीवरी करते समय गोली मार दी गई. पास के गुंडलापोचमपल्ली में रहने वाले उसके परिवार ने घटना की जानकारी दी. अंशुल कुंचा की मौत के मामले पर उनके परिवार ने अहम प्रतिक्रिया दी है. अंशुल की बहन तन्वी कई गंभीर आरोप लगाए हैं. अंशुल की हत्या पांच और छह जून की दरमियानी रात को अमेरिका के फिलाडेल्फिया में कर दी गई. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अंशुल की बहन तन्वी ने बताया कि वह उत्तरी फिलाडेल्फिया, अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और हफ्ते के आखिरी में एक्स्ट्रा इनकम के लिए पिज्जा डिलीवरी करते थे. उनकी बहन ने कहा, 'हमें बताया गया कि उन्हें (अंशुल को) सिर में तीन गोलियां मारी गईं और सड़क पर छोड़ दिया गया.' तन्वी के मुताबिक अंशुल का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ था. उन्होंने कहा कि अंशुल को एक सुनसान इलाके में पिज्जा डिलीवर करने के लिए कहा गया था।

अफगानिस्तान पर भारत ने कसा शिकंजा, सुथार ने लिए तीन विकेट

नई दिल्ली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान ने 113 रन बना लिए हैं. स्टंप्स तक अफगान टीम के पांच विकेट गिर गए हैं. डेब्यू करने वाले मानव सुथार ने अपनी फिरकी से कहर बरपाते हुए 3 विकेट चटका लिए हैं. रहमत शाह ने पारी को संभाला हुआ है, जो 43 रन बनाकर क्रीज पर सेट हो चुके हैं. अफगान टीम अब भी पहली पारी में 451 रनों से पीछे है. बता दें कि टीम इंडिया ने 564 रनों पर पहली पारी घोषित कर दी थी. सरे दिन भारत ने 368/3 के स्कोर से अपनी पारी को आगे बढ़ाया. पहले दिन कप्तान शुभमन गिल शतक पूरा कर चुके थे. ऋषभ पंत ने भी पहले दिन अपना 19वां टेस्ट अर्धशतक पूरा कर लिया था. गिल और पंत के बीच 169 रनों की साझेदारी हुई.

एक समय टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 416 रन बना लिए थे, लेकिन अगले 40 रनों के भीतर शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत का विकेट गिर गया. गिल ने 126 रन, पंत ने 81 रन बनाए. बढ़िया फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरेल केवल 19 रन बना पाए. इस बीच वाशिंगटन सुंदर ने मोर्चा संभाला, जो 52 रन बनाकर नाबाद लौटे. टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 564/8 के स्कोर पर घोषित कर दी.

मुल्लांपुर टेस्ट का फुल कंट्रोल टीम इंडिया के हाथों में है. कप्तान शुभमन गिल डेब्यूटेंट मानव सुथार को जल्दी गेंदबाजी करने लाए. पारी के छठे ओवर में उन्होंने अब्दुल मलिक को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और उन्हें 16 के स्कोर पर आउट कर दिया. मानव सुथार ने ऐसा कहर बरपाया कि 62 के स्कोर पर अफगान टीम 3 विकेट खो चुकी थी. प्रसिद्ध कृष्णा ने भी इस दौरान बढ़िया गेंदबाजी की. दिन का खेल खतम होने तक अफगानिस्तान 451 रनों से पीछे है, वहीं भारत के लिए मानव सुथार ने 3 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा 2 विकेट ले चुके हैं.

अब संन्यास लेकर लीग्स में नहीं खेल पाएंगे भारतीय क्रिकेटर

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) बहुत जल्द अपनी रिटायरमेंट पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर सकती है. बीसीसीआई उन खिलाड़ियों पर लगाम कसने की तैयारी में है, जो संन्यास के तुरंत बाद विदेशी लीगों में खेलने लगते हैं. मौजूदा नियमों के मुताबिक किसी भी एक्टिव भारतीय क्रिकेटर को विदेशी लीगों में खेलने की अनुमति नहीं है, लेकिन रिटायर होने के बाद वह खेल सकता है.

क्या है नई प्रस्तावित रिटायरमेंट पॉलिसी?

BCCI उन खिलाड़ियों की वजह से इस पॉलिसी को लाने पर विचार कर रही है, जो रिटायरमेंट इसलिए ले रहे हैं जिससे विदेशी लीगों में खेल पाएं. खासतौर पर विजय शंकर की वजह से इस मामले ने ज्यादा तूल पकड़ा है. शंकर, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक सप्ताह के भीतर श्रीलंका प्रीमियर लीग में कैंडी रॉयल्स टीम को जॉइन कर लिया. नई प्रस्तावित रिटायरमेंट पॉलिसी कहती है कि रिटायरमेंट के बाद खिलाड़ी पर कूलिंग-ऑफ पीरियड लागू हो जाएगा. इसका मतलब यदि कोई खिलाड़ी संन्यास के बाद विदेशी लीग में खेलता है, तो वह पांच साल तक भारत में किसी भी स्तर का क्रिकेट नहीं खेल पाएगा.

साफ शब्दों में समझ लीजिए कि अगर किसी भारतीय खिलाड़ी ने आज संन्यास लिया है, तो वह अगले 5 साल तक किसी भी विदेशी लीग में भाग नहीं ले पाएगा. अगर वह ऐसा करता है, तो वह अगले 5 साल तक भारत में क्रिकेट किसी भी स्तर का क्रिकेट नहीं खेल सकता.

युवराज-इरफान भी खेलते हैं

विजय शंकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं, जिन्होंने संन्यास के बाद अन्य लीगों में क्रिकेट खेला है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स और लीजेंड्स लीग क्रिकेट में युवराज सिंह, इरफान पठान और हरभजन सिंह समेत कई दिग्गज क्रिकेटर खेलते रहे हैं. उनपर शायद इस रिटायरमेंट पॉलिसी का कोई असर ना पड़े, क्योंकि वे अन्य किसी भी लेवल का क्रिकेट नहीं खेलते हैं.

बाजार से गायब होगा 900 और 950 ML तेल का पैकेट

नई दिल्ली। दअगर आप घर के लिए सरसों, सोयाबीन या रिफाइंड तेल खरीदते हैं, तो अगली बार बाजार में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. केंद्र सरकार ने खाने के तेल की पैकेजिंग को लेकर नया नियम लागू करने का फैसला किया है. अब देश में बिकने वाले ज्यादातर खाने के तेल केवल 9 तय साइज के पैक में ही बेचे जाएंगे. सरकार का कहना है कि इस कदम से ग्राहकों को अलग-अलग ब्रांड के तेल की कीमतों की तुलना करने में आसानी होगी और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कानूनी माप विज्ञान नियमों में बदलाव किया है. सरकार ने कुल 9 मानक पैक साइज तय किए हैं. अब खाने का तेल मुख्य रूप से इन पैक में मिलेगा-200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर।

घरेलू सिलेंडर भी हुआ महंगा बिगड़ा रसोई का बजट

नई दिल्ली। देश में महंगाई ने आम आदमी का दम घोंट दिया है. जरूरत का सामान दिन पर दिन महंगा हो रहा है. दूध, पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के बाद अब देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि गैस कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए का इजाफा कर दिया है. जिसके बाद अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो गई है. दिल्ली-एनसीआर में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम अब 942 रुपए हो गए हैं. वहीं 5 किलो वाले सिलेंडर का रेट 339 रुपए है. इसके अलावा 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3 हजार 113 रुपए 50 पैसे पर कायम है. पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही एलपीजी घेरलू सिलेंडर के दाम बढ़ने के कयास भी लगने शुरू हो गए थे. 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान युद्ध की वजह से सप्लाई में आई दिक्कतों के बावजूद भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए थे. सरकार ने एक मई को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया था. कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए और पांच किलो वाले सिलेंडर के दाम में 261 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद एक जून को कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा हुआ था. एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सप्लाई पूरी तरह सामान्य है।

टीम इंडिया ने 9 साल बाद जीती एशिया कप ट्रॉफी

नई दिल्ली। भारत ने अंडर-18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब जीत लिया है. शुक्रवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने जापान को 4-1 से हराकर ट्रॉफी जीती. इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश पाया था. यह कुल तीसरी बार है जब भारत ने अंडर-18 लेवल पर हॉकी एशिया कप जीता है. इस यादगार जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी. जिस तरह सेमीफाइनल में आशीष पूर्ति ने आखिरी क्वार्टर में मैच का पासा पलट कर रख दिया था. फाइनल में भी उन्होंने 3 गोल करते हुए मैच जिताऊ प्रदर्शन करके दिखाया. मैच के दूसरे मिनट में भी भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली थी और तीसरे क्वार्टर के अंत तक टीम इंडिया 4-0 की बढ़त लेकर जीत की ओर बढ़ रही थी. जापान को चौथे क्वार्टर में चमत्कारी प्रदर्शन करने की जरूरत थी. जापान की तरफ से पूरे मैच में एकमात्र गोल चौथे क्वार्टर में आया, लेकिन यह टीम इंडिया को हराने के लिए काफी नहीं था.

फुटबॉलः भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को रौंदा

नई दिल्ली। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर SAFF वीमेंस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है. यह कुल छठी बार है, जब भारत की महिला फुटबॉल टीम ने यह ट्रॉफी जीती है. खिताबी भिड़ंत गोवा स्थित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में हुई. इससे पहले भारत 2010 से लेकर 2019 तक लगातार 5 बार चैंपियन बना था.फाइनल मैच का पहला गोल भारत की तरफ से हुआ, जब 42वें मिनट में प्यारी खाखा ने टीम इंडिया को 1-0 से बढ़त दिलाई. पहले हाफ के एक्स्ट्रा टाइम में ऋतु चकमा ने गोल करते हुए बांग्लादेश को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया. वहीं जब दूसरा हाफ शुरू हुआ, तो पहले ही मिनट में सनफिदा नोंग्रम ने भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई. मुकाबले का आखिरी गोल भारत की तरफ से हुआ।

सरकार ने दोनों कंपनियों को दिया अल्टीमेटम

BHEL और SAIL से छिन सकता है महारत्न का ताज

नई दिल्ली। देश की दो बड़ी सरकारी कंपनियों BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd) और SAIL (Steel Authority of India Ltd) पर 'महारत्न' दर्जा छिनने का खतरा मंडरा रहा है. केंद्र सरकार ने दोनों कंपनियों को उनके खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए 1 साल का नोटिस दिया है.

कहां हो रही चूक?

कैबिनेट सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समीक्षा नीति की बैठक में यह बात सामने आई कि दोनों कंपनियां महारत्न के सबसे जरूरी वित्तीय मानदंड को पूरा नहीं कर पा रही हैं. किसी भी कंपनी को महारत्न बनाए रखने के लिए पिछले तीन सालों का औसत सालाना शुद्ध लाभ (Profit After Tax-PAT) 5000 करोड़ से अधिक होना चाहिए. इसके विपरीत, देश की कुल 14 महारत्न कंपनियों में से केवल BHEL और SAIL ही ऐसी कंपनियां हैं, जो इस तीन साल वाले मुनाफे के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम हो रही हैं.

क्या होगा अगर छिन गया 'महारत्न' का दर्जा?

अगर ये कंपनियां एक साल के भीतर अपने मुनाफे में सुधार नहीं रखती हैं, तो इन्हें डाउनग्रेड करके 'नवरत्न' की श्रेणी में डाल दिया जाएगा. इससे इनके बोर्ड की वित्तीय स्वायत्ता कम हो जाएगी. अभी महारत्न के तौर पर दोनों कंपनियां बिना सरकारी मंजूरी के सीधे 5000 करोड़ रुपये तक का निवेश या कारोबारी संबंधी फैसला ले सकती हैं. नवरत्न बनते ही इनके निवेश करने की लिमिट घटा दी जाएगी, जो मात्र 1000 करोड़ रुपये रह जाएगी. इससे इनके बड़े प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा.

सरकार का क्या है रुख?

यह पहला मामला है, जब किसी सरकारी पीएसयू को महारत्न का दर्जा वापस लेने की ऐसी सख्त चेतावनी दी गई है. भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय को इन दोनों कंपनियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए एक विस्तृत रिवाइवल प्लान पेश करने के लिए कहा गया है. सरकार ने इस क्रम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों को भी कड़ा कर दिया है. अब CSR फंड और MSME वेंडर्स को समय पर भुगतान न करने जैसे नियमों पर भी इन कंपनियों के नंबर काटे जाएंगे.

साप्ताहिक शहर सत्ता

रायपुर निगम यूजर चार्ज पर सियासत

2022 में भाजपा ने किया था विरोध, अब कांग्रेस ने खोला मोर्चा

रायपुर। रायपुर नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के साथ यूजर चार्ज बढ़ाने का मामला अब राजनीतिक विवाद बन गया है। कांग्रेस के विरोध के बाद अब आम लोग और व्यापारी भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त नहीं है, तब अतिरिक्त शुल्क वसूलना उचित नहीं है। बतादें कि साल 2022 में जब नगर निगम में कांग्रेस की परिषद थी, तब भाजपा ने यूजर चार्ज बढ़ाने का जोरदार विरोध किया था। उस समय मौजूदा महापौर मीनल चौबे नेता प्रतिपक्ष थीं। सामान्य सभा की शुरुआत होते ही भाजपा पार्षदों ने यूजर चार्ज और संपत्ति कर बढ़ाने का विरोध करते हुए हंगामा किया था। आसंदी का घेराव करने पर भाजपा के आठ पार्षदों को निलंबित भी कर दिया गया था।

15 मार्च 2022 को नगर निगम में जब नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने संपत्तिकर और यूजर चार्ज को लेकर चर्चा की मांग की तो सभापति प्रमोद दुबे ने बाद में चर्चा कराने कहा। इस पर भाजपा पार्षदों ने हंगामा किया, डायस के पास जाकर नारेबाजी की। इन्हें निलंबित कर दिया गया। भाजपा पार्षद कार्यालय के बाहर आ गए। महापौर इन्हें मनाने बाहर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके भी आने वाली थीं। उनका संबोधन था। लेकिन भाजपा के लोग अंदर नहीं आए। लिहाजा सभापति प्रमोद दुबे ने सभा स्थगित कर दी। इस दौरान राज्यपाल ने संबोधन दिया। सभा स्थगित होने के बाद जब भाजपा के लोग अंदर आने लगे, तो उन्होंने देखा कि भाजपा पार्षदों की कुर्सियों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे

हुए हैं, तो वे लोग बाहर चले गए। कुर्सियों को लेकर हंगामा किया।

आकाश तिवारी बोले- सफाई नहीं, फिर क्यों बढ़ाया चार्ज?

नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों का असर सबसे ज्यादा आम लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तक शहर के कई इलाकों में कचरे के ढेर लगे हुए थे और कचरा संग्रहण व्यवस्था भी प्रभावित रही। आकाश तिवारी ने कहा कि यूजर चार्ज तभी लिया जाना चाहिए, जब नगर निगम हर घर से नियमित कचरा संग्रहण और बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करे। अभी कई इलाकों में सफाई सही नहीं है। महंगाई के दौर में लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि नगर निगम परिषद को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार विरोध कर रही है और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

महापौर बोलीं- कांग्रेस के समय हुआ था फैसला

वहीं महापौर मीनल चौबे ने कहा कि यूजर चार्ज बढ़ाने की प्रक्रिया नई नहीं है। वर्ष 2022 में तत्कालीन कांग्रेस परिषद ने यूजर चार्ज बढ़ाने का निर्णय लिया था। उस समय भाजपा ने इसका विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस परिषद ने नियमों और राजपत्र का हवाला देकर इसे मंजूरी दी थी।उन्होंने बताया कि डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी के साथ हुए अनुबंध में यह तय किया गया था कि कंपनी को भुगतान यूजर चार्ज से किया जाएगा। यह अनुबंध भी कांग्रेस शासनकाल में ही स्वीकृत हुआ था। यूजर चार्ज में जो बढ़ोतरी हुई है, वह उसी व्यवस्था का हिस्सा है।

सफाई व्यवस्था में सुधार का दावा

महापौर ने माना कि अभी शहर में 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण नहीं हो पा रहा है। हालांकि, नगर निगम की जिम्मेदारी है कि सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। इसके लिए कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलें। उन्होंने कहा कि पिछले साल 2025 में यूजर चार्ज में संशोधन होना था, लेकिन नगर निगम ने इसे लागू नहीं किया था।

भूपेश का निशाना, नीट और सीबीएसई पर बात करें पीएम

शहर सत्ता/रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर शनिवार को तीखा हमला किया। उन्होंने देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई के लिए पीएम को जिम्मेदार ठहराते हुए पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से लेकर खाद्य संकट और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी तीखे सवाल दागे। प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले जाने पर दिए गए बयानों को लेकर भूपेश ने जमकर पलटवार किए। उन्होंने याद दिलाया कि जो खुद राज्यों में सीएम बदलते रहे, वे अब उपदेश दे रहे हैं। राजधानी में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ताश के पत्तों की तरह अपने नेताओं को फेंटते हैं और अब वे दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। देश में बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ियां चल रही हैं, प्रधानमंत्री उसे देखें। कांग्रेस क्या कर रही है और क्या नहीं, यह चिंता करना हम पर छोड़ दें। प्रधानमंत्री को पहले देश को पेट्रोल-डीजल के बारे में बताना चाहिए। वे नीट परीक्षा लीक के बारे में बोलें। सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी, नीट में गड़बड़ी, सभी जगह तो गड़बड़ी हो रही है।

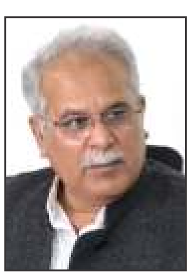

घर-घर चलो अभियान, मंत्री, विधायकों को 50-50 लोगों से मिलना जरूरी

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश भाजपा संगठन का पर्यावरण दिवस से ही कार्यक्रमों के पखवाड़े का आगाज किया गया है। प्रदेश में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह आयोजन केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर किया जा रहा है। पखवाड़े भर के कार्यक्रमों में सबसे बड़ा आयोजन घर-घर चलो महासंपर्क अभियान रहेगा। यह अभियान 8 से 14 जून तक चलेगा। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित पूरा मंत्रिमंडल भी शामिल होगा। इसी के साथ प्रदेश के सभी विधायक, सांसद, सारे जन प्रतिनिधि और भाजपा के छोटे-बड़े नेताओं को आम जनता के घरों तक जाना होगा और उनके साथ संवाद करना होगा। इसके लिए प्रदेश संगठन ने तय किया है कि प्रदेश के मंत्री, विधायक और सांसदों का 50-50 लोगों से मिलना जरूरी होगा। इसी के साथ अन्य के लिए भी लक्ष्य तय किया गया है। इसमें घरों तक पहुंचकर भाजपा नेता केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। किसी कारणवश किसी को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा

होगा तो उनको योजना का लाभ दिलाया जाएगा। इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताया जाएगा। इसके पीछे का एक बड़ा मकसद अगले साल और 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव भी है। इस अभियान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ ही किसी भी क्षेत्र में किसी के घर में दस्तक देंगे। इसी तरह से प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा सहित सभी मंत्री भी आम जनता के घरों तक जाएंगे और उनसे संवाद करेंगे।

किसके लिए कितना लक्ष्य

प्रदेश संगठन ने हर वर्ग के नेताओं के लिए तय किया है कि उनको कितने लोगों से मिलना जरूरी है। इसमें प्रदेश के मंत्री, विधायक और सांसदों के लिए 50-50 लोगों से मिलना जरूरी है। राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए 25-25 लोग, जिला पदाधिकारियों के लिए 15-15 और मंडल अध्यक्षों के लिए 10-10 लोगों से मिलना जरूरी है।

मोहम्मद अकबर ने लगाया आरोप- 22 लाख पेंशनधारियों को 5 महीने से नहीं मिली पेंशन

पूर्व मंत्री ने राज्यपाल को लिखा पत्र, हितग्राही परेशान, जल्दी करें भुगतान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि नहीं मिलने का मुद्दा अब राजभवन तक पहुंच गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल रमन डेका को पत्र लिखकर वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को बकाया राशि दिलाने की मांग की है।

अकबर ने अपने पत्र में कहा है कि, प्रदेश के करीब 22.70 लाख पेंशनधारियों को पिछले लगभग 5 महीने से पेंशन नहीं मिली है। इस कारण गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग हितग्राहियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि महंगाई के दौर में इन लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। कई परिवारों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। पूर्व मंत्री ने कहा कि, प्रदेशभर में चल रहे सुशासन तिहार के दौरान मिलने

वाले आवेदनों और शिकायतों में सबसे अधिक संख्या पेंशन नहीं मिलने से परेशान हितग्राहियों की है। इसके बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि, जब तक केंद्र सरकार से संबंधित मद की राशि प्राप्त नहीं होती, तब तक नियमों के तहत किसी अन्य मद से पेंशनधारियों को भुगतान कराया जाए। बाद में राशि मिलने पर उसका समायोजन किया जा सकता है। अकबर ने कहा कि पहले भी इस तरह की व्यवस्था की जा चुकी है।

संवैधानिक अधिकारों का दिया हवाला

मोहम्मद अकबर ने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेद-154 का उल्लेख करते हुए कहा कि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। उन्होंने राज्यपाल से अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। अकबर ने कहा कि, सरकार को सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की चिंता करनी चाहिए। यदि समय रहते पेंशन राशि जारी नहीं की गई तो लाखों हितग्राहियों की परेशानी और बढ़ सकती है।

मोदी निर्मित महंगाई आम जनता पर कहर बन कर टूट रही: बैज

शहर सत्ता/रायपुर। गैस के दाम बढ़ाने को कांग्रेस ने जनता पर अत्याचार बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि आम लोगों को आज महंगाई का एक और झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस (LPG) सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई है, इसके बाद 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू L P G सिलेंडर की कीमत छत्तीसगढ़ में 1000 रुपये के पार हो गई है। पिछले तीन महीनों में यह दूसरी बार है, जब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले मार्च में भी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। विगत विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने मोदी की गारंटी के नाम पर छत्तीसगढ़ में 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने वादा किया था लेकिन अब यह सरकार वायदाखिलाफी पर उतर आयी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि पिछले महीने ही नौ दिन के भीतर ही तीन-तीन बार मूल्य वृद्धि करके पेट्रोल-डीजल के दाम महंगे किये गए, मई के मध्य से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल 7.50 रुपये से 8 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि हो चुकी है, CNG की कीमतों में भी लगभग 6 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी इस जन विरोधी सरकार ने किया है।

मोदी के 12 साल जनता की बदहाली के 12 साल : कांग्रेस

शहर सत्ता/रायपुर। मोदी सरकार के 12 साल को आम जनता के लिए बदहाली के 12 साल थे। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का विगत 12 साल का कार्यकाल देश की जनता के लिए बेहद निराशाजनक है। उपलब्धि के नाम पर केवल महंगाई की मार, ऐतिहासिक बेरोजगारी, चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर काम करने के चलते देश में बढ़ती असमानता, अमीरी गरीबी की खाई, बढ़ती गरीबी और भुखमरी ही बढ़ी है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार टूट रहा है, मोदी राज में भारत की करेंसी एशिया में सबसे खराब करेंसी साबित हुई है, आर्थिक कुप्रबंधन और गलत नीतियों के चलते देश पर कर्ज का भार बढ़ रहा है आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, हर साल दो करोड़ रोजगार, 2022 तक हर घर में नल, 2024 तक हर सिर पर छत के नाम पर केवल झूठ बोला गया। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद नये प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुये है राज्य सरकार झूठे दावे करती है, आप ही बता दे 2023 के बाद कितने आवास केंद्र ने स्वीकृत किया है?

पेपर लीक के लिए मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दें इस्तीफ़ा : धनंजय

शहर सत्ता/रायपुर। एनएसयूआई नेताओ पर एफआईआर को भाजपा की तानाशाही करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ एवं एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में पेपर लीक के लिये जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग को लेकर शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन किया।जिसे घबराई भाजपा सरकार ने एनएसयूआई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पहले लाठीचार्ज करवाया अब उनके खिलाफ फर्जी आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज किया गया।

खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करें सरकार- कांग्रेस

शहर सत्ता/रायपुर। किसानों की आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध नहीं करवा पाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि यह सरकार जानबूझ कर ठोस प्रयास नहीं कर रही है, पूरे प्रदेश में खरीफ बुवाई का समय आ चुका है और सरकार की बदनीयती से किसानों को यूरिया और डीएपी (DAP) की सीमित आपूर्ति के कारण खाद संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह सरकार तरह-तरह के बहाने बनाकर अड़ंगे लगा रही है। किसानों को पिछले खरीफ सीजन में दिए गए डीएपी की मात्रा से 40 प्रतिशत और यूरिया में 20 प्रतिशत कम देने का तुगलकी फरमान जारी किया गया है।

जशपुर में जल संरक्षण बना जन आंदोलन

सोक पिट, वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच, कंटूर ट्रेंच, आजीविका डबरी और नवा तरिया जैसी संरचनाएं बढ़ा रही जल संचयन क्षमता

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन की दिशा में जशपुर जिला एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभर रहा है। जिले में मनरेगा तथा जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन के लिए विभिन्न नवाचार आधारित संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिससे वर्षा जल संचयन को बढ़ावा मिलने के साथ ग्रामीण आजीविका को भी नई मजबूती मिल रही है। जशपुर जिले में वर्षा जल के अधिकतम संचयन और भू-जल पुनर्भरण के उद्देश्य से घरों, शासकीय संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में सोक पिट बनाए जा रहे हैं। इन संरचनाओं से उपयोग किए गए जल का पुनर्भरण संभव हो रहा है तथा जलभराव की समस्या में भी कमी आ रही है। पहाड़ी एवं ढलान वाले क्षेत्रों में वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच और कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है। ये संरचनाएं वर्षा जल के तीव्र बहाव को नियंत्रित कर मिट्टी के कटाव को रोकने के साथ जल को भूमि में समाहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इससे भू-जल स्तर में सुधार और पर्यावरणीय संतुलन को भी बढ़ावा मिल रहा है।

ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए जिले में आजीविका डबरी निर्माण कार्य तेजी से संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में 495 आजीविका डबरियां निर्माणाधीन हैं। इन डबरियों में वर्षा जल संग्रहित होने से किसानों को रबी एवं ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई सुविधा मिलेगी, वहीं सब्जी उत्पादन, मत्स्य पालन और अन्य आयवर्धक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। जल संरक्षण के क्षेत्र में 'नवा तरिया' अभियान भी उल्लेखनीय परिणाम दे रहा है। नए तालाबों के निर्माण और पुराने जलाशयों के जीर्णोद्धार से जल भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह पर रायपुर में दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेजों की विशेष प्रदर्शनी

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के अवसर पर राजधानी रायपुर में इतिहास और विरासत से जुड़ी एक अनूठी पहल की जा रही है। संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत पुरातत्त्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय द्वारा 8 से 12 जून 2026 तक महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की कला वीथिका (आर्ट गैलरी) में दुर्लभ ऐतिहासिक अभिलेखों की विशेष छायाचित्र प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस आयोजन के माध्यम से आम नागरिकों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, इतिहासकारों तथा संस्कृति प्रेमियों को छत्तीसगढ़ और देश के इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नजदीक से देखने और समझने का अवसर मिलेगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 जून को प्रातः 11 बजे किया जाएगा। इसके बाद यह प्रदर्शनी 12 जून तक प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक आमजन के लिए खुली रहेगी।

प्रदर्शनी में राज्य अभिलेखागार में सुरक्षित उन चयनित ऐतिहासिक दस्तावेजों की डिजिटल प्रतिकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी, जिन्हें राज्य पुनर्गठन के बाद भोपाल से स्कैन कर डिजिटल स्वरूप में प्राप्त किया गया था। ये अभिलेख छत्तीसगढ़ तथा तत्कालीन मध्य प्रांत एवं बरार के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

सीए वित्तीय सलाहकार ही नहीं, व्यवसायों के भरोसेमंद मार्गदर्शक भी : राज्यपाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल खातों और कर संबंधी सलाह देने वाले पेशेवर नहीं हैं, बल्कि वे व्यवसायों को सही दिशा दिखाने वाले भरोसेमंद मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवसाय की सफलता में लेखांकन की भूमिका रीढ़ की हड्डी की तरह होती है और बदलते समय के साथ इसकी जिम्मेदारियां पहले से कहीं अधिक व्यापक हो गई हैं। राज्यपाल रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का आयोजन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की रायपुर शाखा और सेंट्रल इंडिया चार्टर्ड एकाउंटेंट्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन (सिकासा) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। देशभर से आए एक हजार से अधिक सीए विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

राष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन में कहा श्री डेका ने- भरोसा और गोपनीयता ही इस पेशे की सबसे बड़ी पूंजी

राज्यपाल ने कहा कि देश के विकास और सुचारु प्रशासन के लिए कर राजस्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से अपील की कि वे पात्र नागरिकों को कर भुगतान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग कर चुकाना चाहते हैं, लेकिन कई बार जटिल प्रक्रियाएं उनके सामने कठिनाई पैदा करती हैं। विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कर प्रणाली को अधिक सरल और सुगम बनाया जाना चाहिए।

सीजीएमएससी के गोदामों में 400 से अधिक दवाइयाँ उपलब्ध

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) द्वारा राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाओं की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में सीजीएमएससी के विभिन्न गोदामों में 400 से अधिक प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिनका स्वास्थ्य संस्थानों की मांग के अनुसार नियमित रूप से वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 150 अन्य दवाओं के लिए क्रय आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा उनकी आपूर्ति विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। इन दवाओं की प्राप्ति के साथ राज्य में दवा उपलब्धता और अधिक सुदृढ़ होगी।

दवाओं का स्टॉक सुनिश्चित

सीजीएमएससी से मिली जानकारी के अनुसार सामान्य रोगों एवं स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग होने वाली अनेक महत्वपूर्ण दवाएँ वर्तमान में गोदामों में उपलब्ध हैं। इनमें उच्च रक्तचाप (बी पी) के उपचार हेतु एम्लोडिपिन, एनालाप्रिल एवं टेल्मिसार्टन, (डायबिटीज) मधुमेह के लिए ग्लाइमिप्राइड एवं इंसुलिन, बुखार एवं दर्द के लिए पैरासिटामोल 500 मि.ग्रा. टैबलेट, पैरासिटामोल 650 मि.ग्रा. टैबलेट तथा पैरासिटामोल आईवी इंजेक्शन उपलब्ध हैं। इसके साथ ही दर्द निवारक डाइक्लोफेनाक सोडियम इंजेक्शन,संक्रमण के उपचार हेतु एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन + क्लैवुलैनिक एसिड (375 एवं 625 मि.ग्रा.), सेफिक्सिम टैबलेट आईपी 200 मि.ग्रा., मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन तथा अन्य एंटीबायोटिक्स भी उपलब्ध हैं। इसी प्रकार डिहाइड्रेशन एवं आपातकालीन उपचार के लिए डीएनएस, डेक्सट्रोज 5% इंजेक्शन, ओआरएस सैशे, पेट संबंधी समस्याओं के उपचार हेतु ओमेप्राजोल कैप्सूल, पैंटोप्राजोल इंजेक्शन एवं डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट, एलर्जी के लिए सेट्रिजिन टैबलेट तथा कृमि संक्रमण के उपचार हेतु एल्बेंडाजोल टैबलेट जैसी आवश्यक दवाएँ भी उपलब्ध हैं।

सीएम साय ने दो-दो लाख रुपए देकर किया प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित

श्रमिकों के 22 बच्चे दसवीं-बारहवीं की मेरिट लिस्ट में...

रायपुर। कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले श्रमिक परिवारों के बेटे-बेटियोंको छत्तीसगढ़ ने मान दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट सूची में टॉप-10 में स्थान प्राप्त करने वाले श्रमिकों के 22 मेधावी छात्र-छात्राओं को दो-दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया है। इनमें कक्षा 10वीं के 9 तथा कक्षा 12वीं के 13 विद्यार्थी शामिल हैं। ये विद्यार्थी रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, गरियाबंद, सक्ती, बलौदाबाजार, रायगढ़ और कांकेर सहित विभिन्न जिलों से हैं।

सीएम साय ने सम्मानित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि श्रमिक परिवारों के संघर्ष, परिश्रम और संकल्प की प्रेरक कहानी है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे कभी भी स्वयं को किसी से कम न समझें। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक महान व्यक्तित्व साधारण परिवारों से निकलकर

अपनी मेहनत, लगन और शिक्षा के बल पर उच्चतम शिखरों तक पहुंचे हैं। सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार जन्म से लेकर मृत्यु तक श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक कल्याण के लिए लगभग 70 प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने श्रमिक परिवारों से इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने का आग्रह किया तथा उपस्थित हितग्राहियों से कहा कि वे उन श्रमिकों तक भी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं जो अभी इन सुविधाओं से वंचित हैं।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ाने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर श्रम विभाग के सचिव एवं श्रम आयुक्त हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, जनप्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारी, श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी, बड़ी संख्या में श्रमिक तथा उनके परिवारजन उपस्थित थे।

साप्ताहिक शहर सत्ता

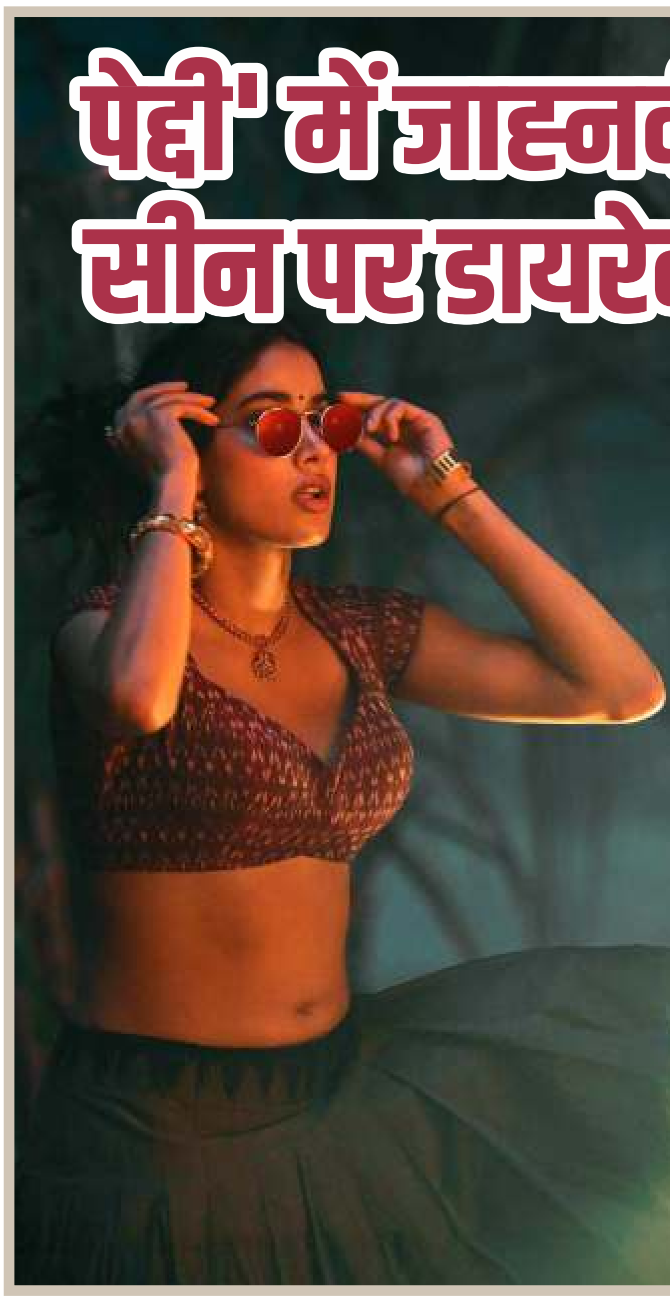

पेद्दी' में जाह्नवी कपूर के विवादित सीन पर डायरेक्टर ने मांगी माफी

बुची बाबू सना ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'एक फिल्ममेकर के तौर पर मेरा मानना है कि सिनेमा का मकसद लोगों का मनोरंजन करना, उन्हें प्रेरित करना और उनसे जुड़ना होना चाहिए. ये कभी भी किसी को असहज या अपमानित महसूस नहीं कराना चाहिए. फिल्म 'पेद्दी' के कुछ सीन को लेकर जो फीडबैक मिला है, हमने उसे गंभीरता से लिया है. मैंने हमेशा महिलाओं का ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन सम्मान किया है. किसी भी महिला किरदार को ऑब्जेक्टिफाई या उनका अनादर करना हमारा इरादा कभी नहीं रहा. अगर फिल्म का कोई हिस्सा इस तरह महसूस हुआ है, तो हम उन भावनाओं का सम्मान करते हैं, उठाई गई चिंताओं को समझते हैं और इसके लिए दिल से माफी मांगते हैं.'उन्होंने आगे लिखा, 'फीडबैक देखने के बाद हमने कुछ हिस्सों में बदलाव करने का फैसला किया है. सिनेमा दर्शकों से जुड़कर ही आगे बढ़ता है और एक कहानीकार के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम बदलती सोच और लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें. हर महिला सम्मान और गरिमा की हकदार है. हम आगे भी ऐसी कहानियां दिखाने की कोशिश करेंगे, जो मजबूत किरदारों को सामने लाएं और इन मूल्यों को बनाए रखें. आप सभी का धन्यवाद, जिन्होंने ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपनी राय शेयर की.' जाह्नवी फिल्म में 'अचियम्मा' का रोल प्ले करती हैं, जो एक पॉलिटिशन की बेटी है. फिल्म में दिखाया गया है कि पेद्दी बने राम चरण को उसकी कमर देखकर उससे प्यार हो जाता है. वो लड़की को बिना उसकी इजाजत किस कर सकता है, जिसे फिल्म में भी जस्टिफाई किया गया है. यही सबसे बड़ी वजह है कि फिल्म 'पेद्दी' ट्रोल्स के निशाने पर है. बता दें कि फिल्म 'पेद्दी' में बोमन ईरानी, दिव्येंदु शर्मा, जगपति बाबू, उपेंद्र लिमये और शिवराजकुमार जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं।

'मुझे लगा मैं वहीं मर जाऊंगा', 70 दिनों तक जेल में रहे विक्रम भट्ट

फिल्ममेकर विक्रम भट्ट इन दिनों अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने अपने मुश्किल समय के बारे में खुलकर बात की, जहां वो एक केस के कारण उदयपुर जेल में 70 दिन तक रहे. इसी बीच उन्होंने खुलासा किया कि उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें लगा कि वो अब नहीं बच पाएंगे.सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू में विक्रम भट्ट ने बताया कि उनके साथ 60 से 80 कैदी थी, जिनके साथ उन्हें इंडिया का एक अलग दृश्य देखने को मिला. उन्होंने कहा, 'वहां मुझे असली दोस्ती का मतलब समझ आया. लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे. मुझे कोई काम नहीं करने देते थे. मेरे लिए खाना लेकर आते थे, कपड़ों का ध्यान रखते थे. जेल के कैदी मुझे प्यार से 'भीष्म पितामह' कहकर बुलाते थे. हर रात दर्जनों कैदी उनके आसपास बैठ जाते थे और उनसे डरावनी कहानियां सुनाने की जिद करते थे. उन्होंने आगे कहा, 'जब मेरी तबीयत खराब थी तब भी जेल स्टाफ और पुलिसकर्मियों ने मेरा साथ दिया. कई लोग ऐसे थे जिनसे मैंने दया की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वही सबसे ज्यादा मददगार साबित हुए. कुछ कैदी तो मेरी सुरक्षा के लिए हमेशा उनके आसपास सोते थे, ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके. ये वही भारत है जो हमारी फिल्में देखता है. जेल में रहकर मुझे दोबारा उन लोगों को समझने का मौका मिला. मैं जान पाया कि वो क्या सोचते हैं, किन बातों पर विश्वास करते हैं और फिल्मों को किस नजर से देखते हैं.'

करोड़ों की मालकिन हैं 'टीवी क्वीन' एकता कपूर

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जितेंद्र की बेटी एकता कपूर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो टीवी इंडस्ट्री की एक जानी-मानी प्रोड्यूसर हैं और छोटे पर्दे की 'क्वीन' के नाम से मशहूर हैं. एकता 7 जून को अपना 51वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी लैविश लाइफस्टाइल और नेटवर्थ के बारे में जानते हैं.

लैविश लाइफ जीती हैं एकता कपूर

एकता का नाम आज सबसे अमीर प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में शुमार है. उनका ये सफर टीवी शो 'हम पांच' से शुरू हुआ था. इसके बाद वो छोटे पर्दे को 'कसौटी जिंदगी की', 'कहानी घर घर की', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'बेकाबू', 'नागिन' और 'बड़े अच्छे लगते हैं' समेत कई हिट शोज दे चुकी हैं. अपने लंबे करियर और सफलता के दम पर उन्होंने अच्छी-खासी संपत्ति भी बनाई है.

95 करोड़ रुपये की मालकिन हैं एकता कपूर

एकता कपूर की नेटवर्थ करीब 95 करोड़ रुपये है. उनकी सालाना कमाई 30 करोड़ रुपये के करीब है. वहीं वो एक महीने में 2.8 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर लेती हैं. एकता कपूर प्रोडक्शन कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स की भी मालिक हैं. इस कंपनी का कुल वैल्यूएशन 420 करोड़ रुपये से अधिक बताया जाता है, जबकि एकता कपूर की इसमें पर्सनल हिस्सेदारी की वैल्यू 190 करोड़ रुपये है.एकता कपूर का मुंबई के जुहू में एक आलीशान बंगला है, जिसका नाम 'कृष्णा' है. इस घर की कीमत 25 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा अल्टामाउंट रोड में टीवी क्वीन का 30 करोड़ रुपये का एक लग्जरी अपार्टमेंट है. एकता कपूर की कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स का कमर्शियल हेडक्वार्टर मुंबई के अंधेरी में स्थित है, जिसकी कीमत 60 करोड़ बताई जाती है. एकता कपूर को लग्जरी गाड़ियों का काफी शौक है. उनके पास 70 लाख रुपये की जैगुआर F-पेस, 1.86 करोड़ रुपये की मर्सिडीज-बेंज S-क्लास मेबैक S 500 और 3.57 करोड़ रुपये की बेंटले कॉन्टिनेंटल GT जैसी कई महंगी गाड़ियां है।

'बंदर' फिल्म में बॉबी देओल के काम को मिल रही तारीफ

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल इन दिनों अपनी नई फिल्म बंदर को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. 5 जून को ही ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसमें बॉबी के अभिनय की जमकर तारीफ हो रही है. साथ ही इसे उनके करियर के सबसे अच्छे परफॉर्मेंस में से एक बताया जा रहा है. इसी बीच उनके भाई और एक्टर सनी देओल भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने ने भी सोशल मीडिया पर एक तस्वीरें शेयर कर अपने भाई पर प्यार लुटाया है.

सनी ने लुटाया प्यार

हाल ही में सनी देओल ने बॉबी देओल और अपनी मां की तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों के बीच का प्यार देखने को मिल रहा हैं. इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'बहुत खुश हूं बॉब!!! लव यू.' बस फिर क्या था, ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है और सभी कमेंट में उनपर जमकर प्यार बरसा रहे है और तारीफ कर रहे हैं.

बता दें कि बॉबी देओल फिल्म 'बंदर' में एक अलग किरदार में नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर आपको तरस आ जाएगा. वो एक ऐसे पॉप स्टार के किरदार में हैं, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और वो जेल चले जाते हैं. फिल्म में बॉबी के साथ सपना पब्बी और सान्या मल्होत्रा भी लीड रोल में हैं, जिनके शानदार अभिनय ने भी सभी को हैरान कर दिया. इसका निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है, जिन्होंने पहले भी कई शानदार प्रोजेक्ट्स से दर्शकों का दिल जीता हैं।

नेशनल अवॉर्ड विजेता सलीम का निधन

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आ रही है. जाने-माने अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर सलीम कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनका शनिवार रात को कोच्चि में निधन हो गया है. अचानक तबीयत बगड़ने के बाद अभिनेता को कोच्चि के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका. सलीम कुमार के निधन की वजह से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता को तबीयत बिगड़ने के बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हॉस्पिटल की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया था कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. सलीम कुमार को ICU में वेंटिलेटर पर रखा गया था और वो डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में थे, इसके बावजूद उनकी हालत में सुधारा नहीं हुआ. आखिरकार सलीम ने 6 जून, शनिवार रात को 10:43 बजे 56 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. अस्पताल ने पुष्टि की है कि उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया. वो कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे।

शरभपुरीय नरेश के उत्तराधिकारियों में महासुदेवराज

डा. देवी प्रसाद वर्मा

महासुदेवराज ने लगभग दस वर्ष राज्य किया। महासुदेवराज के बाद उसका उत्तराधिकारी प्रवरराज हुआ जो कि मानमात्र दुर्ग राज का पुत्र और महासुदेवराज का अनुज था। महाप्रवरराज का छोटा भाई व्याघ्रराज महासुदेवराज के साथ पूर्व राष्ट्र में अपनी सत्ता को संरक्षित करने के लिए संघर्षरत था।

मानमात्र के बाद उसका पुत्र महासुदेवराज उत्तराधिकारी हुआ। अपने राज्य के पश्चिमी सीमावर्ती प्रांतों के विद्रोह को दबाने और अपनी स्थिति को निरापद रखने के लिए महासुदेवराज ने श्रीपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, क्योंकि महासामंत इंद्रबल राज पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। इंद्रबल राज के दो पुत्र ईशानदेव और नन्न राज स्वतंत्र शासक बन चुके थे। उन्हें दबाने में पहले प्रवर राज सफल रहा परन्तु बाद में उसे पराजित होना पड़ा। महासुदेवराज ने लगभग दस वर्ष राज्य किया।

महासुदेवराज के बाद उसका उत्तराधिकारी प्रवरराज हुआ जो कि मानमात्र दुर्ग राज का पुत्र और महासुदेवराज का अनुज था। महाप्रवरराज का छोटा भाई व्याघ्रराज महासुदेवराज के साथ पूर्व राष्ट्र में अपनी सत्ता को संरक्षित करने के लिए संघर्षरत था। महाप्रवरराज के समय में व्याघ्रराज ने पूर्व राष्ट्र में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और बड़ा भाई महाप्रवरराज पश्चिम में विद्रोह दबाने में नन्नराज और ईशानदेव के साथ घमासान युद्ध में रत था, पर वह उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। इसी अवसर का लाभ उठाकर नन्नराज के पुत्र तीतरदेव ने उस पर आक्रमण कर सम्पूर्ण दक्षिण कोसल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।

भेड़ाघाट के रूप में प्रसिद्ध रकसगंडा जलप्रपात

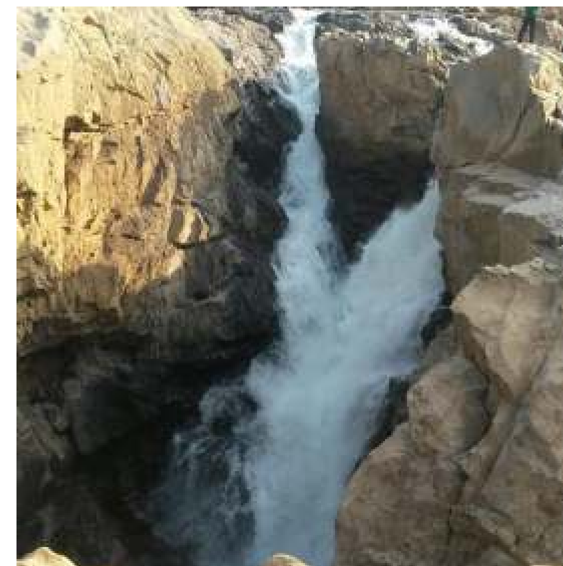

राजपुर जिला के रेन नदी या रिहन्द नदी में स्थित बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक पर्यटन स्थल है-रकसगंडा जलप्रपात। यह रंग-बिरंगे जलधारा के लिए प्रसिद्ध है इस कारण से इसे सुरजपुर का भेड़ाघाट भी कहा जाता है। यह जलप्रपात सुरजपुर से लगभग 120 कि मी, वाड्रफनगर से 60 कि मी की दूरी पर बलंगी के पास ओड़गी विकासखंड में घने जंगलों के बीच स्थित है जिसे रोमांचक पिकनिक के लिए बेहतरीन स्थल माना जाता है। जलप्रपात तीन पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जलधारा लगभग 100 फिट ऊंची चट्टानों से गिरकर नीचे कुंड का निर्माण करता है, यहां से लगभग 100 मीटर लंबी प्राकृतिक सुरंग का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। ऊंची चट्टानों से गिरते हुए पानी के फुहारों से मन रोमांचित हो जाता है। इस क्षेत्र का यह महत्वपूर्ण पिकनिक स्थल है जहां प्रतिवर्ष नए साल के समय अत्यधिक भीड़ होती है।

सिरपुर में अब केवल व्यापार विहार के अवशेष

ललित शर्मा

छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर के स्थल सिरपुर में व्यापार विहार के अवशेष ही मिलते हैं। इस क्षेत्र में प्रवेश करने पर बरगद वृक्ष के दाईं ओर बौद्ध विहार के अवशेष मिलते हैं। इसके समीप ही त्रिदेव मंदिर भी उत्खनन में प्राप्त हुआ है। एक ही अधिष्ठान अधिष्ठान पर तीन गर्भगृह होने के कारण इसे त्रिदेव मंदिर कहा जाता है।

उत्खनन में प्राप्त विशाल व्यापार क्षेत्र को ढाई हजार वर्ष पूर्व योजनाबद्ध रूप से बसाने वाले वास्तुकारों के उत्कृष्ट कौशल को प्रदर्शित करता है। बाजार के मध्य मुख्य मार्ग पर चलते हैं तो तो सारा बाजार जीवंत सा प्रतीत होता है। दुकानों के बरामदे, फिर दुकान और उसके पीछे अनाज रखने की भूमिगत कोठियां पाई गई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि उस काल में वस्तु विनिमय होता था। लोग अपने अनाज लेकर आते थे और बदले में अपने काम की वस्तु खरीद कर ले जाते थे। बाजार क्षेत्र में तीन कुएं प्राप्त हुए हैं, जिससे पेय जल की व्यवस्था होती थी। चूना पत्थर से निर्मित कुएं वर्तमान में सुरक्षित हैं। इस क्षेत्र में खुदाई के दौरान एक भवन से धातु की लगभग 79 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। प्रतिमाओं को देखने से पता चलता है कि धातु शिल्पकला उच्च कोटि की थी। यहां छोटी छोटी नाव के खिलौने भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि उस काल में किस तरह नाव का प्रचलन था, क्योंकि जलमार्ग ही आवागमन का मुख्य साधन था।

भक्तों की मनोकामना पूरी होती है बूढ़ीमाता मंदिर में

डॉ. महेश श्रीवास्तव

छतीसगढ़ के अनेक स्थानों में देवियों की अनेक मान्यताओं वाले मंदिर भक्तों के आस्था के स्थल होते हैं। इसी क्रम में बगीचा विकास खंड के भीतघरा ग्राम के पास पीरईधाम में बूढ़ी माता का मंदिर है। सप्ताह में एक दिन गुरुवार को इनकी पूजा धूप, अगरबत्ती जलाकर विधि विधान से की जाती है। इस पूजा पाठ में सम्मिलित होने बिरहोर जनजाति के लोग दूर दूर से यहां आते हैं। बीमारी और दर्द से निजात पाने के लिए बूढ़ीमाता को चढ़ाई गई अगरबत्ती का भभूत (राख) का उपयोग किया जाता है इसके तहत थोड़ी भभूत इनके द्वारा प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है और शेष को शरीर में लगाया जाता है। यदि किसी पीड़ति व्यक्ति की पीड़ा दूर हो जाती है तो वे इस मंदिर में बलि देने मंदिर में आते हैं। माता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है जिसके कारण भक्तों की भीड़ वर्ष भर मंदिर में होती है।

अनेक उपलब्धियां समाहित हैं महादेवा कसेकेरा गांव में

सुअरमारगढ़ क्षेत्र में महादेवा कसेकेरा एक प्राचीन ग्राम है। यहां एक कि मी दूरी तक गुप्तकालीन प्राचीन अवशेष बिखरे पड़े हैं। लोक मान्यता है कि वृन्दावन के पिरवर वंशीय राजा कसेरु सिंह ने इस गांव को बसाया, इस कारण गांव का नाम कसेकेरा पड़ा। दूसरी मान्यता के अनुसार यहां केले की खूब खेती होती थी। कसेकेरा से भलेसर तक सुरंग की बात बताई जाती है। कालांतर में गांव ने काफी विकास किया है। वर्तमान में स्कूल, ग्राम पंचायत मुख्यालय, पटवारी, ग्राम सहायक, बैंक और पोस्ट आफिस की सुविधा यहां उपलब्ध हो गई है। बागवानी, कृषि कार्य, अखाड़ा, व्यायाम, संगीत आदि की शिक्षा यहां दी जाती है। पूरा क्षेत्र नदियों एवं घने जंगलों तथा पहाड़ियों से घिरा होने के कारण आश्रमो की याद दिलाता है।

मासूम सुमना तुझे सलाम

दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त 12 साल की सुमना जाते-जाते दे गई जिंदगी

प्रमुख संवाददाता/विकास यादव
मोबाईल नंबर 9425528000

दर्द से कराहती और दम तोड़ती लाडली को देखना किसी भी मां-बाप के लिए अभिशाप सा है। उसकी तंदरूस्ती के लिए दर-दर भटकने के बाद भी जब मासूम बेटी की सांसें थम जाएं तब किसी मां-बाप पर क्या बीतेगी इसका अहसास करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बारह वर्षीय सुमना कुंडु के माता-पिता अपनी नन्ही परी का अंत जान गए थे। तब भी उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया जो समाज और प्रदेश के लिए प्रेरणादायी बन गया है। बेटी को तो उन्होने नहीं बचा पाया लेकिन मासूम सुमना के माता-पिता ने बेटी के अंतिम सफर में जाने से पहले उसकी दोनों किडनियों से एक 15 वर्षीय बच्चे और 45 वर्षीय युवक को किडनी डोनेट कर नई जिंदगी दी।

गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी गई श्रद्धांजलि

मानवता के इस महान कार्य के सम्मान में सुमना को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनका अंगदान न केवल दो मरीजों के लिए जीवनदान बना, बल्कि समाज को यह संदेश भी दे गया कि मौत के बाद भी किसी का जीवन कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है।

- रायपुर एम्स में अंगदान से 2 मरीजों को मिला नया जीवन
- 9 दिनों तक आईसीयू में इलाज और वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी
- मौत के बाद भी जिंदगी देने वाली को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर
- एम्स रायपुर में पहला बाल चिकित्सा मृत अंग दान

शहर सत्ता/रायपुर। महज 12 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली सुमना कुंडू अब दो जरूरतमंद मरीजों की जिंदगी में हमेशा जीवित रहेगी। ब्रेन डेथ घोषित होने के बाद उनके माता-पिता ने साहसिक और मानवीय निर्णय लेते हुए उनकी दोनों किडनी दान कर दीं। इस अंगदान के जरिए एम्स रायपुर में भर्ती दो मरीजों को नया जीवन मिला है। सुमना कुंडू (12 वर्ष 4 माह) को 29 मई 2026 को एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया था। वह पिक्नोडाइसोस्टोसिस (Pyknodysostosis with Intracranial Hypertension and Bilateral Optic Atrophy) जैसी दुर्लभ और गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। लगातार 9 दिनों तक आईसीयू में इलाज और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखने के बावजूद डॉक्टर के प्रयास सफल नहीं हो सके। निर्धारित चिकित्सकीय प्रक्रिया के बाद उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया गया।

माता-पिता ने लिया प्रेरणादायी फैसला

दुख की इस घड़ी में अंग प्रत्यारोपण समन्वयक अंबे पटेल और विनीता पटेल ने परिवार को अंगदान के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सुमना के पिता लक्ष्मण कुंडु और माता सरस्वती कुंडु ने समाजहित में उनकी दोनों किडनी दान करने की सहमति दी। परिवार के इस फैसले को चिकित्सा जगत और समाज में मानवता की मिसाल माना जा रहा है।

दो मरीजों को मिला नया जीवन

SOTTO छत्तीसगढ़ के दिशानिर्देशों के अनुसार, किडनी का आवंटन प्रतीक्षा सूची में शामिल मरीजों को किया गया। पहली किडनी रायपुर के टाटीबंध निवासी 15 वर्षीय किशोर को प्रत्यारोपित की गई, जो पिछले तीन वर्षों से डायलिसिस पर था। दूसरी किडनी रायपुर निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति को प्रत्यारोपित की गई, जो मूल रूप से मध्यप्रदेश के बालाघाट का रहने वाला है और पिछले पांच वर्षों से डायलिसिस पर था। दोनों प्रत्यारोपण सफल रहे हैं और दोनों मरीज फिलहाल किडनी ट्रांसप्लांट आईसीयू में स्वस्थ हो रहे हैं।

कई विभागों के समन्वय से सफल हुआ ऑपरेशन

किडनी प्रत्यारोपण की प्रक्रिया एम्स रायपुर के यूरोलॉजी विभाग के डॉ. अमित आर. शर्मा के नेतृत्व में पूरी की गई। इसमें डॉ. दीपक बिस्वाल, डॉ. राघवेंद्र, नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉ. विनय राठौर और डॉ. नीलम मरावी सहित एनेस्थीसिया टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह पूरा अभियान एम्स रायपुर और SOTTO छत्तीसगढ़ के साथ नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, फोरेंसिक मेडिसिन और PICU विभागों के समन्वय से संभव हो सका।

अंगदान मानवता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति

SOTTO छत्तीसगढ़ के संयुक्त संचालक डॉ. वरुण अग्रवाल ने कहा कि अंगदान केवल चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानवता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। एक परिवार का निर्णय कई परिवारों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आता है। वहीं SOTTO छत्तीसगढ़ की IEC एवं मीडिया कंसल्टेंट गीतिका ब्रह्मभट्ट त्रिपाठी ने कहा कि सुमना का अंगदान समाज में जागरूकता का प्रेरक उदाहरण है, जो लोगों को मृत्यु के बाद भी जीवन बांटने की प्रेरणा देगा।

पहला बाल चिकित्सा मृत अंग दान

दान की गई एक किडनी रायपुर के एक 15 वर्षीय लड़के को प्रत्यारोपित की गई, जो पिछले तीन वर्षों से डायलिसिस पर निर्भर था, जबकि दूसरी किडनी मध्य प्रदेश के बालाघाट के एक 45 वर्षीय मरीज को दी गई, जो पिछले पांच वर्षों से डायलिसिस करा रहे थे। दोनों ट्रांसप्लांट प्रक्रियाएं पूरी तरह सफल रहीं और दोनों प्राप्तकर्ता किडनी ट्रांसप्लांट आईसीयू में तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। इस जटिल सर्जिकल ट्रांसप्लांट को यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. अमित आर. शर्मा, डॉ. दीपक बिस्वाल और डॉ. राघवेंद्र ने नेफ्रोलॉजी टीम (जिसमें डॉ. विनय राठौर और डॉ. नीलम मरावी शामिल थे) और एनेस्थिसियोलॉजी टीम (जिसका नेतृत्व प्रो. मोनिका खेत्रपाल और डॉ. सरिता रामचंद्रानी कर रही थीं) के साथ मिलकर अंजाम दिया। यह ऐतिहासिक चिकित्सा उपलब्धि बाल रोग, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, एनेस्थिसियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, फॉरेंसिक मेडिसिन विभागों और सोटो-छत्तीसगढ़ के आपसी और सुचारू समन्वय के प्रयासों से ही संभव हो सकी।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27